घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 134- मंगलवार 17- मार्च 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

राज्यसभा में एलपीजी संकट पर हंगामा...लोकसभा में बिना हंगामे के प्रश्नकाल पूरा

सरकार को पहले से पता था,इंतजाम क्यों नहीं किया : कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे

नई दिल्ली,16 मार्च 2026। बजट सत्र के दूसरे फेज में सोमवार को लोकसभा में पहली बार प्रश्नकाल बिना किसी हंगामे के पूरा हुआ। इधर राज्यसभा में एलपीजी सिलेंडर के संकट को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में दावा किया कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित कर रही है। अगर सरकार समय रहते इंतजाम कर लेती,तो हालात इतने खराब नहीं होते। इस पर भाजपा सांसद जेपी नड्डा ने खड़गे को टोका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपदा में भी राजनीति कर रही है। इसके बाद भी खड़गे ने बोलना जारी रखा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेता जवाब नहीं सुनते है।

लोकसभा में बिना हंगामे के प्रश्नकाल पूरा हुआ...

लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कुछ विपक्षी सांसदों ने अपने मुद्दे तुरंत उठाने की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन्हें दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल खत्म होने के बाद बोलने का मौका दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण,केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांसदे के सवालों के जवाब दिए। राज्यसभा में कार्यकाल पूरा होने पर रंजन गोगोई को विदाई दी गई। 9 मार्च से शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले हफ्ते में विपक्ष के विरोध के कारण सुबह 11 बजे से 12 बजे तक होने वाला प्रश्नकाल पूरा नहीं हो पा रहा था। पंजाब से आप सांसद राघव चड्ढा ने विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार से मांग की है कि शादीशुदा जोड़ों को संयुक्त रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि पति-पत्नी मिलकर घर की जिम्मेदारियां और खर्च उठाते हैं,इसलिए उन्हें संयुक्त आईटीआर दाखिल करने का विकल्प मिलना चाहिए।

एलपीजी संकट पर खड़गे बोले...पहले से पता था तो व्यवस्था क्यों नहीं की?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में दावा किया कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है,लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित कर रही है। जब भारत सरकार ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क कर रही थी,तब यह भी साफ करना चाहिए था कि आने वाले समय में तेल और गैस की कमी हो सकती है। खड़गे ने कहा कि अगर सरकार समय रहते व्यवस्था कर लेती,तो हालात इतने खराब नहीं होते। जब सरकार को पहले से स्थिति का अंदाजा था,तो समय पर जरूरी इंतजाम क्यों नहीं किए गए?

खड़गे के बयान पर नड्डा बोले...अराजकता लाने का प्रयास कर रहा विपक्ष

नेता सदन जेपी नड्डा ने खड़गे की बात पर आपत्ति की और कहा कि यह शून्यकाल है और एलओपी तीन मिनट बोल चुके हैं। नियम सभी के लिए समान होते हैं। हमें दु:ख है कि विपक्ष देश में विपत्ति काल में भी राजनीति करने से पीछे नहीं हटते। यह विपत्ति भारत के कारण नहीं आई है। हम सब जानते हैं कि ये क्राइसिस आई है। कांग्रेस का नेता सिलेंडर की होल्डिंग में पकड़ा गया है। ये जनता को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं।

वित्त मंत्री बोलीं- डीआरटी मामलों के निपटारे के लिए 2026 में 4 विशेष लोक अदालतें होंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि 2026 में कर्ज वसूली अधिकरण और कर्ज वसूली अपीलीय अधिकरण में लंबित मामलों के निपटारे के लिए चार विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। इन अधिकरणों में लंबित अधिकांश मामले बड़े मूल्य के हैं, जिनमें आमतौर पर 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की राशि शामिल है। बड़े मामलों के तेजी से निपटारे के लिए कुछ डीआरटी को खास तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक वाले मामलों की सुनवाई के लिए तय किया गया है। इसके अलावा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लोक अदालत जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान माध्यमों के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कटक के मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग

10 मरीजों की मौत,11 कर्मचारी भी घायल

कटक,16 मार्च 2026। ओडिशा के कटक में सोमवार तड़के एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग लग गई। इस घटना में अब तक 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि आग सुबह करीब 2:30 से 3:00 बजे के बीच लगी। मामले को लेकर एक अधिकारी ने बताया, आग अस्पताल के ट्रॉमा केयर विभाग के आईसीयू में भड़की थी और देखते ही देखते आग ने बड़ा रूप ले लिया। यहां उन मरीजों का इलाज चल रहा था जिनकी हालत बहुत गंभीर थी। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें तुरंत अस्पताल पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने अभियान चलाकर आग पर काबू पाया। मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में अस्पताल के 11 कर्मचारी भी झुलस गए। कुल 23 मरीजों को आनन-फानन में दूसरे विभागों और वार्डों में शिफ्ट किया गया। इस बचाव कार्य में अस्पताल के कर्मचारियों, पुलिस और मरीजों के साथ आए लोगों ने भी सहयोग किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायल मरीजों के इलाज में कोई कमी न रहे। उन्होंने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पहुंचे अस्पताल

हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां के हालात का जायजा लिया और भर्ती मरीजों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट-सर्किट हो सकती है। आग ने ट्रॉमा केयर आईसीयू के साथ-साथ पास के कुछ और वार्डों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि सात गंभीर मरीजों की मौत शिफ्टिंग के दौरान ही हो गई थी। इसके बाद तीन और मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

सरकार ने हर मृतक के परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। फिलहाल अस्पताल में स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है और मामले की गहराई से जांच हो रही है।

चुनाव आयोग ने असम,केरल,पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी की...नामांकन प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली,16 मार्च 2026। चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को असम,केरल एवं पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव और गोवा, कर्नाटक,नगालैंड एवं त्रिपुरा की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। इसी के साथ इन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी। चुनाव आयोग ने बतया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारियों को आचार संहिता तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। एमसीसी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होगा। आयोग ने सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति से चुनावी डिफेसमेंट हटाने,सरकारी गाड़ी या घर का गलत इस्तेमाल रोकने और सरकारी खर्च पर विज्ञापन जारी करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने नागरिकों की निजता का रोकने के लिए आम लोगों के घरों के बाहर कोई प्रदर्शन या धरना देने पर रोक लगाई है। और मालिक की सहमति के बिना जमीन, इमारत या दीवारों का इस्तेमाल झंडे,बैनर या पोस्टर के लिए इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई है। आयोग ने शिकायतों के लिए आयोग ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है,जिसमें 1950 कॉल सेंटर नंबर का प्रयोग किया जाएगा। इसके जरिए आम नागरिक या राजनीतिक दल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज करा पाएंगे। इसके अलावा नागरिक और राजनीतिक दल सी-विजिल ऐप का इस्तेमाल करके एमसीसी उल्लंघन की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वॉड और 5200 से अधिक स्टैटिक सर्विलांस टीम तैनात की गई हैं। आयोग ने बताया कि राजनीतिक दलों को मीटिंग और जुलूस से पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करना होगा ताकि ट्रैफिक और सुरक्षा का इंतजाम किया जा सके। लाउडस्पीकर और अन्य सुविधाओं के लिए जरूरी अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

होर्मुज से एलपीजी लेकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा भारतीय जहाज शिवालिक

नई दिल्ली,16 मार्च 2026। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है। खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर भारतीय ध्वज वाला शिवालिक जहाज 45,000 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) लेकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट बंदरगाह पहुंच गया है। दूसरा जहाज नंदा के भी जल्द आने के बाद देश में रसोई गैस की किल्लत कम होने के आसार हैं। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर संयुक्त हमले के चलते हॉर्मुज जलडमरूमध्य में फंसा भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर शिवालिक 'शिवालिक' 45,000 टन एलपीजी लेकर सोमवार को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच गया है। युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकले इस जहाज से देशभर में चल रहा एलपीजी संकट दूर होने की उम्मीद है। इससे पहले जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया था कि भारतीय ध्वज वाला एलपीजी वाहक शिवालिक आज शाम 5 बजे पहुंच जाएगा। कुमार ने कहा कि इसके आगमन से पहले मुद्रा बंदरगाह पर दस्तावेजीकरण, प्राथमिकता बर्थिंग और सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है, ताकि माल के निर्वहन में कोई देरी न हो। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में कोई घटना सामने नहीं आई है और हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। हम प्रत्येक जहाज और उसके चालक दल के संपर्क में हैं। कुमार ने कहा कि 611 भारतीय नाविकों के साथ 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम में बने हुए हैं।

बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए के सभी पांचों उम्मीदवारों की जीत,सम्राट चौधरी ने दी बधाई

नई दिल्ली,16 मार्च 2026। बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी पांचों सीटों पर जीत दर्ज की है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पांचों उम्मीदवारों की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें जीत की बधाई दी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन और न्याय के साथ विकास के नीति की जीत है। उन्होंने एनडीए के सभी विधायकों का आभार जताते हुए कहा कि सभी ने एकजुट होकर उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों ने अपनी पार्टी,एनडीए,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए वोट किया है। यह उनके एनडीए के प्रति समर्पण और बिहार के विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि वे पांच बार विधायक और बिहार में एनडीए सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। बिहार के विकास में उनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। वे हमेशा जनता के सरोकार की राजनीति करते हैं। उपमुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि विधानसभा के बाद अब वे उच्च सदन राज्यसभा की गरिमा को और बढ़ाने का काम करेंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में उन्होंने बिहार के विकास को नया आयाम दिया है। 2005 से पहले के जंगलराज वाले बिहार को अपने दूरदर्शी नेतृत्व से उन्होंने तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता है। उनके मार्गदर्शन में बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। नीतीश कुमार के लंबे संसदीय अनुभव का लाभ अब राज्यसभा को भी मिलेगा। उपमुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय के पुरोधा स्व. कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोकमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भी पुनः राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इनके राजनीतिक अनुभव का लाभ राज्यसभा को मिलता रहेगा। साथ ही,उन्होंने शिवेश राम के राज्यसभा सदस्य बनने पर भी शुभकामनाएं दी। चौधरी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ,सबका विकास के ध्येय पर राजनीति करती है। शिवेश राम का राज्यसभा के लिए चुना जाना इसका जीवंत उदाहरण है।

केरल विधानसभा चुनाव...बीजेपी की पहली लिस्ट जारी,47 उम्मीदवारों के नाम

नई दिल्ली,16 मार्च 2026। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करते हुए 140 में से 47 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी ने राज्य के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को नेमोम सीट से मैदान में उतारा है। चंद्रशेखर 2024 लोकसभा चुनाव में केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर से हार गए थे। पार्टी ने के. सुरेंद्रन को मंजेश्वर सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं नव्या हरिदास को कोझिकोड नॉर्थ से टिकट दिया गया है। इसके अलावा एडवोकेट जॉर्ज कुरियन को कंजिरापल्ली और वी. मुरलीधरन को काझाकूट्टम से उतारा है। चुनाव आयोग ने रविवार को चार राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का शेड्यूल घोषित किया था। केरल में 9 अप्रेल को वोटिंग है और नतीजे 4 मई को आएंगे।

केरल-दक्षिण का इकलौता राज्य जहां लेफ्ट सत्ता में: देश का इकलौता राज्य है,जहां आज भी लेफ्ट सत्ता में है। यहां सत्ता बदलने की परंपरा रही है,लेकिन 2021 में वाम मोर्चा ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस गठबंधन की कोशिश इस बार एंटी इनकम्बेंसी को कैश करानी की रहेगी। वहीं, बीजेपी अब तक केरल में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां उसने त्रिशूर लोकसभा सीट जीती थी। इसके अलावा दिसंबर 2025 में भी बीजेपी ने पहली बार त्रिवेंद्रम (तिरुवनंतपुरम) नगर निगम का चुनाव जीता।

बच्चों को स्मार्टफोन न दें,परिवार के साथ समय बिताएं : योगी आदित्यनाथ

जालोर,16 मार्च 2026। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मातृशक्ति से आह्वान किया कि छोटी उम्र के बच्चों को रोने या नाराज होने दें,लेकिन उन्हें स्मार्टफोन बिल्कुल न दें। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन का अत्यधिक प्रयोग बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और यह डिप्रेशन जैसी समस्याओं को बढ़ा रहा है। सोमवार को रत्नेश्वर महादेव मंदिर के 375 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय महायज्ञ और विशाल धर्मसभा में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बच्चे जितना समय स्मार्टफोन पर बिताते हैं, उतना समय यदि अच्छी पुस्तकों के अध्ययन,योग और व्यायाम में लगाएं तो उनका जीवन अधिक बेहतर और व्यवस्थित बन सकता है। धर्मसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी को सलाह दी कि स्मार्टफोन का प्रयोग केवल आवश्यकता के अनुसार ही करें। परिवार के लिए समय निकालें और आपस में संवाद बनाए रखें। उन्होंने कहा कि भोजन और पूजा के समय फोन उठाने से बचें और बाद में कॉल बैक करें।

बंगाल में चुनाव से पहले मुख्य सचिव-डीजीपी को हटाया

कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत 6 अधिकारी बदले,आयोग बोला-ये अफसर चुनाव से दूर रहेंगे

नई दिल्ली,16 मार्च 2026। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के दूसरे ही दिन चुनाव आयोग ने 6 अफसरों का तबादला कर दिया। आयोग ने पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को डीजीपी बनाया है। वहीं, आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटा दिया है। उनकी जगह 1993 बैच के आईएएस दुष्मंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। सुप्रतिम सरकार की जगह अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। साथ ही राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा की जगह

संघमित्रा घोष, गृह सचिव

1997 बैच की आईएएस अफसर संघमित्रा घोष को गृह सचिव बनाया गया है। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। नटराजन रमेश बाबू को सुधार सेवा महानिदेशक बनाया गया है। अजय मुकुंद रानाडे को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और कानून-व्यवस्था का पद दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनाव से जुड़े पद पर तैनात नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने रविवार को बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। बंगाल की 294 सीटों पर 2 फेज में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को रिजल्ट आएगा।

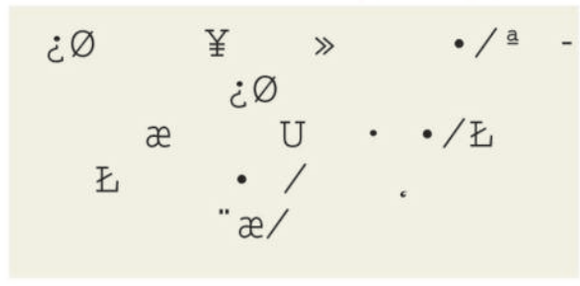

भाजपा की 144 नामों की पहली लिस्ट जारी...बंगाल में सीएम ममता की सीट से चुनाव लड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी

नई दिल्ली,16 मार्च 2026। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से भी चुनाव लड़ाने का फैसला किया है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं और वर्तमान में यहां से विधायक भी हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी के करीबी रहे सुवेंदु अधिकारी के भवानीपुर से चुनाव लड़ने के फैसले से एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक टकराव की प्रबल संभावना पैदा हो गई है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद भवानीपुर से टीएमसी विधायक सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने ममता के लिए अपनी सीट छोड़ने का फैसला किया था और यहां से वह उपचुनाव में जीतकर बंगाल विधानसभा में पहुंची थीं। भाजपा द्वारा इस निर्वाचन क्षेत्र से अधिकारी को मैदान में उतारने का निर्णय तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व को उसके गढ़ में चुनौती देने की आक्रामक रणनीति का संकेत देता है।

बीजेपी ने 41 विधायकों को किया रिपीट : भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता और महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के परिवार से संबंध रखने वाले सौमित्र चट्टोपाध्याय को नैहाटी से उम्मीदवार नामित किया गया है। घोषित उम्मीदवारों में से 41 वर्तमान विधायक और 3 पूर्व विधायक हैं। बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को खड़गपुर सदर से मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अपनी फायरब्रांड महिला नेता अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है, जबकि पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता राशबेहारी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने कालीगंज से बापन घोष, डायमंड हार्बर से दीपक कुमार हलदर, आसनसोल उत्तर से कृष्णेंदु मुकर्जी, हासन से निखिल बनर्जी, कूचबिहार उत्तर से सुकुमार रॉय और सिलीगुड़ी से शंकर घोष को मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट में घोषित 144 उम्मीदवारों में से 57 ऐसे उम्मीदवार हैं जो प्रोफेशनल और सोशल बैकग्राउंड से आते हैं। पार्टी ने इन चेहरों को प्रमुखता देते हुए शिक्षा, सामाजिक सेवा और पेशेवर अनुभव वाले लोगों को मैदान में उतारा है।

संपादकीय

वांगचुक की रिहाई

आखिरकार गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हटाने से जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई हो गई है। वांगचुक गत वर्ष सितंबर से जोधपुर जेल में बंद थे, जिसको लेकर विपक्षी राजनीतिक दल व विभिन्न सामाजिक संगठन तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे हैं। अब सरकार की दलील है कि यह फैसला लद्दाख में शांति,स्थिरता और संवाद का माहौल बनाने के लिये लिया गया है। वहीं विपक्षी राजनीतिक दलों का कहना है कि 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी। गिरफ्तारी का आधार मजबूत न होने पर केंद्र सरकार को उन्हें रिहा करने को बाध्य होना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जलवायु कार्यकर्ता, अभिनव शैक्षिक व वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए चर्चित सोनम वांगचुक को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बीते साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल, वे लंबे समय से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने वाले आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने कई बार अनशन किया। पदयात्रा के जरिये दिल्ली पहुंचकर भी उन्होंने अनशन किया था। लेकिन सितंबर में आंदोलन के हिंसक होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं केंद्र सरकार की दलील है कि क्षेत्र के लोगों की मांगों का समाधान निकालने के लिये लद्दाख के अलग-अलग समुदायों, नेताओं और संगठनों से निरंतर बातचीत के प्रयास जारी हैं। साथ ही लद्दाख के लिये सभी जरूरी सुरक्षा उपाय करने की बात कही गई है।

वहीं विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी की तार्किकता क्या थी? क्या लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहने की आजादी का अतिक्रमण नहीं हो रहा है? नागरिक संगठनों से जुड़े लोगों ने वांगचुक को उनके ठंडे प्रदेश लद्दाख से 1400 किमी दूर गर्म प्रदेश राजस्थान की जोधपुर जेल में रखने पर भी सवाल उठाये थे। उल्लेखनीय है कि बीते माह शीर्ष अदालत ने भी सोनम वांगचुक की खराब सेहत के मद्देनजर,उनकी हिरासत पर पुनर्विचार करने को कहा था। दरअसल,बार-बार पेटदर्द की शिकायत पर उनकी पत्नी ने विशेषज्ञ डॉक्टरों से जांच करवाने के लिये आवेदन किया था। साथ ही कोर्ट से मासिक स्वास्थ्य रिपोर्ट की भी मांग की थी। तब शीर्ष अदालत की पीठ ने टिप्पणी की थी कि यदि हिरासत के आदेश में कानूनी त्रुटियां हैं तो इसे रद्द भी किया जा सकता है। वहीं सरकार की दलील थी कि आंदोलन को हिंसक बनाने में भूमिका के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने के पर्याप्त कारण मौजूद थे। वहीं विपक्षी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वांगचुक को 170 दिन हिरासत में रखने का हिसाब कौन देगा? वे इस मामले में केंद्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। अन्य विपक्षी दल भी इस रिहाई के बाद केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बेजा इस्तेमाल के आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि लद्दाख के पर्यावरण व हक की मांग उठाने की कीमत वांगचुक ने चुकाई है।

राजनीतिक जंग के आगाज में लोकतांत्रिक मूल्य फिर दांव पर

पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान कम चरणों में संपन्न कराया जा रहा है,जो प्रशासनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा सकता है। असम,केरल और पुडुचेरी में जहां 9 अप्रैल को मतदान प्रस्तावित है,वहीं तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं-पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा। इन चुनावों की ओर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं,क्योंकि इनके परिणाम केवल इन राज्यों की राजनीति ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित कर सकते हैं...

ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं होते,बल्कि वे लोकतंत्र की परिपक्वता, जनविश्वास और राजनीतिक संस्कृति की परीक्षा भी होते हैं। जब किसी राज्य या क्षेत्र में चुनाव की घोषणा होती है तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं,आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता है और दल अपने-अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं। किंतु इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में एक संस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है-भारत का चुनाव आयोग। यही संस्था सुनिश्चित करती है कि चुनाव स्वतंत्र,निष्पक्ष और हिंसा-मुक्त वातावरण में संपन्न हों। इस बार असम, पश्चिम बंगाल,तमिलनाडु और केरल जैसे चार बड़े राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही देश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन पांचों स्थानों की कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और देश के 17.4 करोड मतदाताओं के मन एवं मानसिकता की जानकारी भी मिलेगी। इन चुनावों का महत्व केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य की भी परीक्षा है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में लंबे समय से राजनीतिक संघर्ष और टकराव की स्थिति देखने को मिलती रही है। वहां सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा के कारण कई बार चुनावी हिंसा और राजनीतिक तनाव की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। इसलिए यह चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि यह भी एक कसौटी है कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया हिंसा और भय से मुक्त रहकर संपन्न हो सकती है।

लोकतंत्र का मूल आधार यह है कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी दबाव,भय या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में इस आदर्श को बनाए रखना आसान नहीं है। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। इसके लिए आयोग को सुरक्षा बलों की तैनाती,मतदान केंद्रों की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की सुरक्षा और मतदाता सूची की शुद्धता जैसे अनेक पहलुओं पर लगातार निगरानी रखनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं के आचरण पर भी नजर रखना जरूरी होता है ताकि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो। इन चुनावों के संदर्भ में पश्चिम बंगाल विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। लंबे समय से वहां राजनीतिक हिंसा और टकराव की घटनाएं सामने आती रही हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस बार वहां सत्ता परिवर्तन की संभावना के कारण राजनीतिक संघर्ष और तीखा हो सकता है।

सत्तारूढ़ नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली ममता बनर्जी की सरकार के सामने सत्ता बनाए रखने की चुनौती है,वहीं विपक्ष अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस परिस्थिति में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखे। दूसरी ओर केरल और तमिलनाडु की राजनीति भी अपने विशिष्ट स्वरूप के कारण चर्चा में रहती है। केरल में आमतौर पर सत्ता दो प्रमुख राजनीतिक मोर्चों के बीच बदलती रही है,जबकि तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रीय दलों के प्रभाव के लिए जानी जाती है। इन राज्यों में चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र होती है,किंतु अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान की परंपरा भी देखने को मिलती है। असम की स्थिति भी अलग है,जहां पूर्वोत्तर भारत की राजनीति के संदर्भ में चुनाव के परिणाम महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि वहां सत्तारूढ़ दल फिर से सत्ता में लौटता है तो यह क्षेत्रीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाएगा। हालांकि इन सभी चुनावों के संदर्भ में एक प्रश्न लगातार उठता है कि क्या राजनीतिक दल लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करने के लिए पर्याप्त गंभीर हैं। चुनावी राजनीति में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है,किंतु जब यह प्रतिस्पर्धा हिंसा,घृणा और असहिष्णुता में बदल जाती है तो लोकतंत्र की मूल भावना को चोट पहुंचती है। दुर्भाग्य से कई बार राजनीतिक दल चुनाव जीतने की होड़ में लोकतांत्रिक शालीनता को नजरअंदाज कर देते हैं। आरोप-प्रत्यारोप, व्यक्तिगत हमले और हिंसक घटनाएं इस प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। इस स्थिति में यह केवल चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं रह जाती कि वह चुनाव को निष्पक्ष बनाए। राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वे लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखें। यदि दल स्वयं ही आचार संहिता का सम्मान करें और अपने कार्यकर्ताओं को संयमित आचरण के लिए प्रेरित करें तो चुनावी प्रक्रिया कहीं अधिक स्वस्थ और सकारात्मक बन सकती है। लोकतंत्र की सफलता केवल संस्थाओं पर निर्भर नहीं करती,बल्कि राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक चेतना पर भी निर्भर करती है।

इसके साथ ही मतदाताओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है। यदि मतदाता जागरूक और सजग हों तो वे ऐसे नेताओं और दलों को प्रोत्साहित करेंगे जो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। मतदाताओं को यह समझना होगा कि उनका वोट केवल एक राजनीतिक विकल्प नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा तय करने वाला निर्णय भी है। इन पांच क्षेत्रों में होने वाले चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे यह संदेश देंगे कि भारत का लोकतंत्र किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि ये चुनाव शांतिपूर्ण,निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न होते हैं तो यह न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण होगा। भारत को अक्सर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है,इसलिए यहां होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नजर रहती है।

निश्चित तसौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं हैं,बल्कि वे लोकतंत्र के मूल्यों की परीक्षा भी हैं। असम,पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु,केरल और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि इन चुनावों में राजनीतिक दल संयम और जिम्मेदारी का परिचय दें,चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता और दृढ़ता बनाए रखे तथा मतदाता जागरूकता के साथ मतदान करें,तो यह लोकतंत्र की शक्ति को और अधिक सुदृढ़ करेगा। प्रश्न यह है कि क्या हम इन चुनावों के माध्यम से एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे,जिसमें लोकतंत्र केवल मतपेटियों तक सीमित न रहकर शालीनता,सहिष्णुता और जनविश्वास की भावना को भी मजबूत करे। यही वह कसौटी है जिस पर इन चुनावों की सफलता या असफलता का वास्तविक मूल्यांकन किया जाएगा।

मुनाफाखोरी की बीमारी दुस्साहस में नहीं आई कोई कमी

इस पर तनिक भी आश्चर्य नहीं कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के चलते ऊर्जा आपूर्ति का संकट उभरते ही देश में रसोई गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई। यद्यपि सरकार ने इसे रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया, पर लगता नहीं कि इससे जमाखोरों और मुनाफाखोरों के दुस्साहस में कोई कमी आई है। इसका प्रमाण यह है कि उनके खिलाफ छापेमारी के दौरान कई शहरों में रसोई गैस सिलिंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले पकड़े गए। कई ने दर्जनों रसोई गैस सिलिंडर चोरी-छिपे जमा कर रखे थे। इनमें कुछ नेता और अन्य प्रभावशाली लोग भी हैं। इसी तरह उन मुनाफाखोरों की गिनती करना भी कठिन है, जो महंगे दामों पर रसोई गैस सिलिंडर बेच रहे थे। ऐसे तत्वों की सक्रियता का एक कारण संबंधित अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत भी होती है। वे भी बहती गंगा में हाथ धोने लगते हैं और इस तरह आम जनता एवं सरकार का संकट बढ़ाते हैं। अपने देश में किसी भी संकट के समय आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी बहुत आम है। कोविड महामारी के समय जब सारा देश संकट में था, तब भी कुछ दवाओं के साथ कई आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी देखने को मिली थी। यह भी किसी से छिपा नहीं कि अपने यहां कभी प्याज, कभी उर्वरकों तो कभी किसी अन्य वस्तु की जमाखोरी होने लगती है। इसका मकसद मुनाफाखोरी करना ही होता है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग सदैव इसकी ताक में रहते हैं कि कब किसी वस्तु के उत्पादन अथवा उसकी आपूर्ति में कमी के आसार दिखें तो वे खुद को जमाखोर में तब्दील कर मुनाफाखोरी करें। आपदा को अपना धंधा बनाने वाले ऐसे लोग सभ्य समाज के शत्रु ही कहे जाएंगे। चूंकि नैतिकता और सदाचार की कमी के चलते जमाखोरी और कालाबाजारी एक सामाजिक बुराई का रूप ले चुकी है, इसलिए आवश्यक केवल यह नहीं कि रसोई गैस सिलिंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहे लोगों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाए, बल्कि यह भी है कि उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया जाए। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ उन्हें तीन महीने से लेकर सात वर्ष तक की सजा देने का प्रविधान है, लेकिन आखिर कितने ऐसे मुनाफाखोर हैं, जिन्हें सात वर्ष की सजा मिलती है? अधिकतर तो येन-केन-प्रकारेण बिना किसी दंड के छूट जाते हैं या फिर मामूली जुर्माना देकर बच निकलते हैं। उचित यह होगा कि ऐसे लोगों को ऐसी कठोर सजा दी जाए, जो नजीर बने। गंभीर मामलों में जमाखोरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त की जानी चाहिए।

ईद-उल-फित्र,की असल रूह और खूबसूरती रिश्तों की कद्र करने में है

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह

ईद-उल-फित्र महज एक त्यौहार नहीं,बल्कि यह परवरदिगार-ए-आलम की तरफ़ से अपने बंदों के लिए एक अजीम ईनाम है, जो रमजान-उल-मुबारक के पूरे महीने की इबादतों,रियाजतों और सब्र-ओ-जब्त के बाद अता किया जाता है। इस्लाम में ईद मनाने का असल मक़सद उस रूहानी कामयाबी का जश्न मनाना है,जो एक मोमिन ने भूख, प्यास और नफ्स पर क़ाबू पाकर हासिल की होती है,यह शुक्रगुजारी का वह दिन है जब बंदा अपने रब के हुजूर सजदा-रेज होकर इस बात का शुक्र अदा करता है कि उसे नेकियां करने की तौफ़ीक़ मिली। लेकिन इस मुक़द्दस दिन की रूहानी अहमियत के साथ-साथ इसका एक इंसानी और जज़्बाती पहलू भी है,जो वक्त की गर्दिश के साथ अपनी रंगत बदलता रहता है,क्योंकि हक़ीक़त यही है कि 'हर ईद एक जैसी नहीं होती।' कभी यह दिन मसर्रत की उस चोटी पर होता है जहाँ घर के हर कोने में अपनों के कहकहे गूँजते हैं,दस्तरखानों पर पकवानों की महक के साथ अपनों का साथ रूह को सरशार कर देता है और इंसान का दिल पूरी तरह मुतमईन होता है कि उसकी क़ायनात उसके पास है। मगर वक्त की बेरुख़ी और हालात की तब्दीली इंसान को एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ वही ईद जो कभी सबसे ज़्यादा खुशी का सबब थी,अब महज एक खामोशी और तन्हाई के लिबास में लिपटी हुई महसूस होती है। लोग बदल जाते हैं,कुछ मौत की आग़ोश में सो जाते हैं तो कुछ जिंदगी की जद्दोजहद में दूर निकल जाते हैं और पीछे रह जाती है तो सिर्फ वह कसक जो नए कपड़ों और महफ़िलों के बीच भी दिल को तड़पाती रहती है। यह 'हजूम में तन्हाई' का वह अलमिया है जहाँ इंसान दुनिया को तो मुस्कुरा कर ईद मुबारक कहता है,मगर उसके अंदर का खालीपन उसे गुजरे हुए उन लम्हों की याद दिलाता है जो अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। ईद की असल रूह और खूबसूरती उन रिश्तों की क़द्र करने में है जो अभी हमारे पास हैं क्योंकि गुजरा हुआ वक्त और बिछड़े हुए लोग सिर्फ़ यादों के झरोखों में ही जिंदा रहते हैं, और इंसान का दिल अक्सर भरी महफिल में भी किसी एक शख्स की कमी को शिद्दत से महसूस करता है। इसी क़ैफ़ियत और ईद के जज़्बात को शायर ने इन अजकार में पिरोया है,

'ऐ ईद के चाँद! क्यों तू हमें रुलाता है,
बिछड़े हुए अपनों की हमें याद दिलाता है।
यूँ तो हर तरफ है रौनक
और खुशियों का समां,
मगर खाली घर हमें अपनी तन्हाई सुनाता है।
और इस बदलते हुए मंजर और यादों के
तसल्सुल पर एक और लाजवाब शेर है,
'सब गले मिल के मुबारकबाद देते रहे,
पर मुझे गुजरा हुआ एक दौर याद आया है।
अब के भी ईद गई यूँ ही दबे पाँव मेरे,
दिल में जो दर्द था वो आँखों में उतर आया है।

यह मुकम्मल मंजरकशी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी खुशियों और ग़मों का एक हसीन इंतजाम है, जहाँ हर ईद एक नया तजुर्बा और एक नई सीख लेकर आती है।

कविता

मोनिका डागा
'आनंद'

मेरा वाला ऐसा नहीं

घर की ना घाट की लव-जिहाद की शिकार बनी स्त्रियाँ,
कुचली जाती है हँसती-खेलती 'आनंद' कोमल कलियाँ,
अपनों के ही खिलाफ़ बगावत करती नासमझ बेटियाँ,
प्यार में धोखा खा ये गुमसुम गुमराह आधी टूटी स्त्रियाँ।

जिनके लिए संजोएं माँ-बाप ने जीवन के रंगीन सपनें,
वो प्रेम में पड़ अनदेखा करे कौन पराए कौन है अपने,
आज को धकेल गर्त में छोड़ देती परिवार को तड़पनें,
ज्ञानेंद्रियों को नकार बस प्रेम की माला लगती जपने ।

आँखों पर पट्टी बाँध वे कहती मेरा वाला ऐसा नहीं,
विपरीत लिंग आकर्षण में गुम हो जाती हैं वे कहीं,
प्यार में अंधे होकर संस्कारों को भुलाना सही नहीं,
ये भी सच हर प्रेमी युगल शाहरुख खान-गौरी नहीं ।

पवित्र प्रेम को वो शारीरिक आर्थिक चमक समझती,
वास्तविकता से परे प्रेमी के प्रेम-जाल में नित रमती,
अपने स्वतंत्र अस्तित्व की बलि देने में देर नहीं लगाती,
स्वयं भविष्य को उजाड़ गलत फैसले की मार सहती ।

अंततः शर्मिंदा हो गलतियों पर करें वे इंसाफ की टेर,
मगर समय हाथ से निकल जाता हो जाती है बहुत देर,
बटोरती कुछ दिन वो फिर अखबारों की सुर्खियाँ घनेर,
पर सच यहीं मासूम सी जिंदगी हो जाती रेत जैसे ढेर ।

झाड़ू बेचने वाला...!

संजय एम तराणेकर
इन्दौर (मध्य प्रदेश)

सुबह की पहली किरण के संग,
कंधे पर उम्मीदों का बोझ लिए,
निकल पड़ता है वह चुपचाप
गली-गली में अपना रोज लिए।
'झाड़ू ले लो... झाड़ू!' की ध्वनि
सन्नाटे को चीरकर जाती है,
हर दरवाजे पर उसकी आशा
धीरे से दस्तक देकर आती है।
कभी कोई दाम कम कर देता,
कभी कोई यूँ ही टाल देता,
पर वह मुस्कुराकर आगे बढ़ता,
दिल का दर्द भी संभाल लेता।
उसकी झाड़ू सिर्फ कूड़ा नहीं,
घर-आँगन की धूल हटाती है,
कौन समझे उस कमजोर की
जिंदगी कितनी झाड़ू लगाती।
शाम को जब थका-हारा लौटे,
थैली में थोड़े से होते हैं रूपये
अपने बच्चों की हँसी देखकर
उसके सारे दुख होते हैं छोटे।
वह जानता और समझता है
कल फिर सुबह सूरज निकलेगा,
और वह फिर गलियों में जाएगा,
'झाड़ू ले लो...झाड़ू' पुकारेगा,
और उम्मीदों से अपना घर,
रोशन करने का खूवाब सजाएगा।

आदर्श श्मशान

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा

टिकैतगंज गांव में जब 'घपलेराम' ने प्रधानी का चुनाव जीतने के लिए मृत्यु को ही अपना चुनावी मुद्दा बनाया, तो यमराज भी स्वर्ग में बैठकर अपनी भैंसे की लगाम ढीली कर हंसने लगे होंगे। घपलेराम का तर्क था कि जन्म लेना तो एक निजी दुर्घटना है,लेकिन मरना एक 'सामुदायिक उत्सव' होना चाहिए। उन्होंने गांव के जर्जर श्मशान को 'मुक्तिधाम लग्जरी रिजॉर्ट' बनाने का वादा किया,जहाँ चिता की राख से सीधे आर्गेनिक खाद बनेगी और स्वर्ग जाने वालों के लिए 'वीआईपी गेट' लगवाया जाएगा। उनके चुनावी कार्यालय में विकास की फाइलें इतनी धूल खा रही थीं कि अगर उन्हें झाड़ा जाता, तो पूरे गांव को दमे की बीमारी मुफ्त में मिल जाती। घपलेराम कहते थे कि जनता को रोटी,कपड़ा और मकान से ज्यादा 'गरिमामय विदाई' की जरूरत है, क्योंकि जिंदा आदमी तो शिकायत करता है,लेकिन मुर्दा हमेशा मौन समर्थन देता है। चुनाव से ठीक एक रात पहले घपलेराम ने गांव के बीचों-बीच एक विशाल सोने जैसा दिखने वाला संदूक रखा और घोषणा की कि इसमें 'अमरता का अमृत' रखा है। उन्होंने गांव वालों को पट्टी पढ़ाई कि जो भी उन्हें वोट देगा,उसे एक विशेष 'अमरता कोड' मिलेगा,जिसे यमराज के दूत भी नहीं काट पाएंगे। पूरे गांव में होड़ मच गई,लोग अपनी आधी-अधूरी जिंदगी छोड़कर उस संदूक के दर्शन के लिए कतार में लग गए। घपलेराम ने संदूक पर लेजर लाइटें लगवा दीं और वहां एक छोटा सा फॉर्म भरवाना शुरू किया–'अमरता प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र'।

विपक्षी उम्मीदवार 'ढपोरशंख' इस नई तकनीक के सामने चारों खाने चित थे,क्योंकि वे केवल जीवितों के लिए वादे कर रहे थे,जबकि घपलेराम ने परलोक में भी अपनी ब्रांच खोल दी थी। जनता को लगा कि बस,अब न बुढ़ापा आएगा और न ही सरकारी अस्पताल के धक्के खाने पड़ेंगे। जिस सुबह घपलेराम भारी बहुमत से विजयी घोषित हुए,पूरा गांव ढोल-नगाड़ों के साथ उस संदूक का ताला खुलवाने पहुँचा। घपलेराम ने बड़े शान से ताला खोला,तो संदूक के अंदर से केवल एक फटा हुआ आईना और एक प्लास्टिक का खिलौना-सा सांप निकला। जनता के बीच सन्नाटा छा गया,तभी घपलेराम दहाड़ कर बोले– 'भाइयों और बहनों! अमृत तो आप सबके भीतर की 'उम्मीद' थी जिसे मैंने पी लिया और अब मैं अगले पांच साल के लिए अजेय हो गया हूँ। और यह सांप इसलिए है ताकि आपको याद रहे कि राजनीति में जो सीधा चलता है,वह सपेरे की टोकरी में बंद हो जाता है।' जनता हक्की-बक्की अपनी ही परछाईं उस फटे आईने में देख रही थी,जबकि घपलेराम अपनी जीत का गुलाल उड़ाते हुए 'मुक्तिधाम' की बाउंड्री वॉल का टेंडर पास कराने शहर रवाना हो गए।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटाराअम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

अंबिकापुर में रसोई गैस संकट जारी सिलेंडर के लिए भटक रहे लोग

एजेंसियों के बाहर लग रही लंबी कतारें,ब्लैक में 1800 से 2000 रुपए तक बिक रहा गैस सिलेंडर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

शहर में रसोई गैस को लेकर बनी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिला प्रशासन भले ही गैस की कमी की खबरों को अफवाह बता रहा हो,लेकिन हकीकत यह है कि आम लोगों को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। शहर के कई इलाकों में लोग गैस के लिए भटकने को मजबूर हैं और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गैस की उपलब्धता काफी कम हो गई है। कई उपभोक्ताओं ने समय पर बुकिंग कराने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिलने की शिकायत की है। इससे घरों की रसोई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। लोग सुबह से ही गैस एजेंसियों और वितरण केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कई बार उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। गैस की कमी का फायदा उठाकर कुछ लोग कालाबाजारी भी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार जहां सामान्य स्थिति में सिलेंडर तय कीमत पर मिलना चाहिए, वहीं इन दिनों ब्लैक में एक सिलेंडर 1800 से 2000 रुपए तक में बेचा जा रहा है। मजबूरी में कई लोग महंगे दामों पर गैस खरीदने को विवश हैं।

छोटे सिलेंडर की गैस भी महंगी

छोटे सिलेंडरों में गैस भरवाने की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। पहले गैस ब्लॉक में करीब 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गैस मिल जाती थी, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर लगभग 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित

इस संकट का सबसे ज्यादा असर किराये के कमरों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों पर पड़ रहा है। शहर में बड़ी संख्या में छात्र छोटे सिलेंडर या मिनी गैस के सहारे खाना बनाते हैं। लेकिन गैस उपलब्ध नहीं होने से उन्हें होटल या ढाबों में खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनका खर्च भी बढ़ गया है। कई छात्र परेशानी से तंग आकर फिलहाल अपने घर लौट गए हैं।

व्यवस्था सुधारने की मांग

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच कर गैस वितरण व्यवस्था सुधारने की मांग की है। साथ ही कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है, ताकि लोगों को समय पर और उचित कीमत पर गैस उपलब्ध हो सके।

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा : उड़नदस्ता टीम का निरीक्षण,लखनपुर केन्द्र में नकल के 2 प्रकरण दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर द्वारा आयोजित हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा-2026 के अंतर्गत सोमवार को हिन्दी विषय की परीक्षा जिले में शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुई। जिले के निर्धारित 10 परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर द्वारा गठित विशेष उड़नदस्ता दल ने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उड़नदस्ता टीम ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनपुर,शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लहपटरा,शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बतौली तथा शासकीय नगर पालिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा केन्द्र क्रमांक 1224, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनपुर में अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए 02 परीक्षार्थी पकड़े गए। इन परीक्षार्थियों (अनुक्रमांक 21224260130 एवं 21224260005) के विरुद्ध नियमानुसार नकल प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित पाई गई। हिन्दी विषय की परीक्षा के लिए जिले में कुल 1769 परीक्षार्थी पंजीकृत थे,जिनमें से 1668 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए,जबकि 101 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा आगामी परीक्षाओं को भी निष्पक्ष एवं नकलविहीन संपन्न कराने के लिए सतत निगरानी रखी जा रही है।

अफीम खेती मामले में बलरामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई,बिहार-झारखंड से दो सरगना गिरफ्तार

-संवाददाता-
बलरामपुर,16 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बड़े पैमाने पर सामने आई अवैध अफीम की खेती के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। मामले की एंड टू एंड विवेचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए बलरामपुर पुलिस ने बिहार और झारखंड से दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। इससे पहले इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है जानकारी अनुसार थाना कुसमी और थाना कोरंधा क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती के दो बड़े मामले सामने आए थे। कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम त्रिपुरी घोसराडांड़ तथा कोरंधा थाना क्षेत्र के ग्राम तुर्रीपानी खजूरी में पुलिस, प्रशासन और एफएसएल की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अफीम की खेती पकड़ी थी। कार्रवाई के दौरान ग्राम त्रिपुरी से 4344.569 किलोग्राम अफीम की फसल, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 75 लाख रुपये आंकी गई, जबकि ग्राम तुर्रीपानी खजूरी से 1883.76 किलोग्राम अफीम,जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये बताई गई,जब्त की गई थी। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 18 के तहत प्रकरण दर्ज कर 9 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा और पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के निर्देशन में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया था। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने झारखंड और बिहार के कई संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी। इसी दौरान थाना कुसमी के अपराध क्रमांक 26/2026 में वांछित आरोपी पैरू सिंह भोक्ता (35 वर्ष) निवासी सोमिया,थाना बाराचट्टी, जिला गया (बिहार) को गया से गिरफ्तार किया गया। वहीं थाना कोरंधा के अपराध क्रमांक 04/2026 के सरगना आरोपी भूपेंद्र उरांव उर्फ भूपेंदरा उरांव (38 वर्ष) निवासी ग्राम चाया, पोस्ट कुंदा, पंचायत बोथाडीह, जिला चतरा (झारखंड) को उसके गांव से घेराबंदी कर पकड़ा गया।

दोस्त ने टांगी और डंडे से मारकर की हत्या,शव डबरी में फेंका शादी में शामिल होने आया था युवक,शराब पीने के दौरान हुआ विवाद,एक आरोपी गिरफ्तार,अन्य की तलाश...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पोतका जमतीपारा में एक युवक ने अपने ही दोस्त की टांगी और डंडे से मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को करीब डेढ़ किलोमीटर दूर दो फीट पानी से भरी डबरी में फेंक दिया। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। पड़ोस में शादी का कार्यक्रम होने के कारण रात में किसी को घटना की भनक नहीं लगी। जानकारी के अनुसार मृतक शीतल (22) निवासी हनुमानगढ़, थाना उदयपुर रविवार रात शादी समारोह में शामिल होने पोतका जमतीपारा गया था। यहां उसका दोस्त प्रमोद गोड़ (22) रहता है। रात में प्रमोद ने शीतल को अपने घर बुलाया, जहां दोनों ने बैठकर शराब पी। बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि प्रमोद ने टांगी और डंडे से हमला कर शीतल की हत्या कर दी।

डेढ़ किमी दूर डबरी में फेंका शव : हत्या के बाद आरोपी ने शव को करीब डेढ़ किलोमीटर दूर ले जाकर दो फीट पानी से भरी डबरी में फेंक दिया। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने डबरी के पास खून से सनी बोरी और मोबाइल पड़ा देखा,जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

पंप लगाकर खाली कराया पानी

सूचना मिलते ही उदयपुर थाना प्रभारी शिशिर कांत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को निकालने के लिए डबरी का पानी पंप लगाकर खाली कराया गया। इसके बाद शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

एक आरोपी गिरफ्तार,अन्य पर संदेह

पुलिस ने मामले में आरोपी प्रमोद गोड़ को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि हत्या की इस वारदात में अन्य लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए शव को डेढ़ किलोमीटर दूर ले जाकर फेंकना संभव नहीं माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

नगदी लूटपाट का आरोपी गिरफ्तार...आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त बुलेट मोटरसायकल एवं 1000 रुपये नगद किया गया जप्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

प्रार्थी संदीप लकड़ा साकिन ग्राम मरकाडाड थाना राजपुर जिला बलरामपुर द्वारा दिनांक 14/03/26 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी दिनांक 11/03/26 को शाम करीब 6-00 बजे प्रार्थी अपने ससुर के साथ मोटर सायकल से हॉस्पिटल से गाधीचौक की ओर आ रहा था कि राज पोल्ट्री फार्म के पास पहुंचा ही था तभी एक काला रंग का बुलेट मोटर सायकल में सवार एक व्यक्ति आया और प्रार्थी का रास्ता रोकते हुये धमकी देते हुये बोलने लगा की तुम्हे रूकने के लिये बोला तो क्यो नहीं रूका, बोलते हुए गाली गलौज करते हुये धक्का मुक्की करने लगा, और स्वयं को आरटीओ का अधिकारी शहजोर अली होना बताकर जबरन प्रार्थी के पर्स में रखा 10,000 रुपये एवं शर्ट के पाकिट में रखा 10000 रुपये कुल 20 हजार रुपये नगद रकम लूट कर अपने पास रख लिया और पर्स को प्रार्थी की ओर फेक दिया और धमकी देते हुये वहा से भगा दिया, बाद में प्रार्थी अपने परिचितो को घटना की बात बताया फिर आरटीओ आफिस में जाकर पता करने पर कोई इस नाम का अधिकारी नही होना पाया, फिर पता करने पर पता चला कि उसका नाम शहजोर अली पिता अयुब अली निवासी सतीपारा इरानी मोहल्ला का रहने वाला है, शहजोर अली प्रार्थी को डरा धमकाकर 20000 रुपये का लूट किया है, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 143/26 धारा 126(2), 309(4),204 बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। मामले को संज्ञान मे लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा पुलिस टीम को मामले मे त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण के आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम मे थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पत्ता तलाश कर पकड़कर हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम शहजोर अली पिता अयुब अली उम्र 24 वर्ष साकिन सतीपारा थाना कोतवाली अंबिकापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया,आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त बुलेट मोटरसायकल एवं 1000 रुपये नगदी जप्त किया गया है,आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, गिरफ्तार आरोपी द्वारा पूर्व मे संजय पार्क के सामने से एक अन्य व्यक्ति से 1130 रुपये का लूटपाट किया गया था, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 118/26 धारा 309(3) बी.एन.एस का अपराध पंजीबद्ध किया गया था,उक्त मामले मे थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

जिले में 17 मार्च से वृहद स्वैच्छिक रक्तदान अभियान होगी प्रारंभ,8 मई तक विभिन्न संस्थानों में लगेंगे शिविर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

कलेक्टर सह अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा सरगुजा के निर्देशानुसार जिले में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वृहद स्वैच्छिक रक्तदान अभियान संचालित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सह सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा सरगुजा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अभियान के अंतर्गत 17 मार्च 2026 से 08 मई 2026 तक जिले के विभिन्न शासकीय, अशासकीय, शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थानों के समन्वय से चरणबद्ध रूप से स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उक्त रक्तदान शिविरों का आयोजन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा सरगुजा के समन्वय से किया जाएगा। वहीं राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध ब्लड सेंटर की चिकित्सकीय एवं तकनीकी टीम द्वारा रक्त संग्रहण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के तहत जिले के विभिन्न महाविद्यालयों, शासकीय कार्यालयों, सामाजिक संगठनों तथा अन्य संस्थानों में युवाओं और आम नागरिकों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सह सचिव,भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा सरगुजा ने जिले के सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों और संस्थानों से इस स्वैच्छिक रक्तदान अभियान में बढ़-चढ़कर सहभागिता करने की अपील की है।

माई विलेज चैलेंज के तहत शॉर्ट वीडियो प्रतियोगिता और क्विज का आयोजन

वीबी-जी रामजी एक्ट,2025 के लिए लोगो डिजाइन करने वाले विजेता को मिलेगा 50,000 रुपये का पुरस्कार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा देशभर के युवाओं को ग्रामीण विकास एवं आजीविका से जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान 'वीबी-जी रामजी यूथ डिजिटल कैंपेन' की शुरुआत की गई है। यह अभियान माई भारत पोर्टल के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से युवा विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेकर ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे। अभियान के अंतर्गत 'माई विलेज चैलेंज' नाम से राष्ट्रीय स्तर पर शॉर्ट वीडियो/रील प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें प्रतिभागी किसी भी भारतीय भाषा में 30 से 60 सेकंड की अवधि का वीडियो तैयार कर माई भारत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले वीडियो की अधिकतम साइज 25 एमबी निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाग ले सकते हैं। चयनित प्रतिभागियों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा करने का अवसर भी मिलेगा।

इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागी अपने गांव के विकास,रोजगार सृजन तथा आजीविका संवर्धन में अधिनियम की भूमिका को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे। इसी प्रकार MY Bharat Portal पर विकसित भारत-जी रामजी अधिनियम से संबंधित क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इसमें प्रतिभागियों को निर्धारित समयावधि में 20 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त MyGov पोर्टल पर विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट के लिए 'विकसित भारत-जी रामजी एक्ट, 2025' का लोगो डिजाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसा लोगो चुनना है जो अधिनियम के तहत समावेशी विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण प्रगति के संदेश को प्रभावी रूप से दर्शा सके। चयनित सर्वश्रेष्ठ लोगो को आधिकारिक लोगो के रूप में अपनाया जाएगा तथा भविष्य में प्रचार-प्रसार और अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वाले विजेता को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से 50,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चयनित लोगो के सभी बौद्धिक संपदा अधिकार भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास रहेंगे। लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक युवा MY Bharat Portal एवं MyGov पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कर प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं।

इंडसइंड बैंक कर्मचारी ने किश्त के नाम पर हड़पे 7.50 लाख रुपए,एफआईआर दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

इंडसइंड बैंक के एक कर्मचारी पर लोन की किश्त के नाम पर अवैध वसूली कर रुपए धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बैंक की जांच में करीब 7.50 लाख रुपए के गबन का खुलासा हुआ है। बैंक प्रबंधन की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार इंडसइंड बैंक के मैनेजर अरुण सर्राफ ने गांधीनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि बैंक में कार्यरत कर्मचारी सागीर अहमद ने मार्च 2024 से जनवरी 2025 के बीच वाहन फाइनेंस कराने वाले कई खाताधारकों से लोन की किश्तें नगद में वसूल की है। कर्मचारी ने ग्राहकों से नगद राशि लेने के बाद उन्हें किसी प्रकार की रसीद नहीं दी और न ही उक्त राशि बैंक के ऋण खाते में जमा की। बैंक की जांच में कुल 7 लाख 50 हजार 390 रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक की ओर से दोपहिया वाहन फाइनेंस कराने वाले ग्राहकों को किश्त जमा नहीं होने का नोटिस भेजा गया। नोटिस मिलने पर वाहन मालिकों ने बैंक को बताया कि उन्होंने पहले ही किश्त की राशि कर्मचारी सागीर अहमद को नगद में दे दी थी। बैंक की जांच में सामने आया है कि गड़बड़ी छिपाने के लिए जमा पर्चियों और खातों के दस्तावेजों में हेराफेरी की गई। आरोप है कि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर गबन की रकम को छिपाने की कोशिश की गई। मैनेजर की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी सागीर अहमद के खिलाफ धारा 316(5) और 318(4) के तहत अपराध दर्ज किया है।

दो महीने,दर्जनों खुलासे...फिर भी जिम्मेदार

गायब! सूरजपुर धान घोटाले की पूरी कहानी

धान घोटाले का सचः जनवरी-फरवरी में खुलती रहीं परतें,जिम्मेदार अब भी सुरक्षित

- कागजों में धान,गोदाम में सवाल! दो महीने की रिपोर्टिंग से हिला सिस्टम
- 11 करोड़ का धान खेल : खुलासे पर खुलासे,लेकिन कार्रवाई अब भी अधूरी
- धान खरीदी का 'महाखेल': खबरें छपीं, जांच हुई...लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं
- घोटाले की टाइमलाइन : 65 हजार क्विंटल से 11 करोड़ तक,कैसे खुलता गया राज
- सूरजपुर धान घोटालाः मीडिया ने निभाई जिम्मेदारी,सिस्टम अब भी चुप

धान खरीदी का सच : रिकॉर्ड कुछ और,हकीकत कुछ और

दो महीने की इन्वेस्टिगेशन : धान घोटाले की परतें खुलीं,पर दोषी अब भी पर्दे में...

धान खरीदी केंद्र से करोड़ों के खेल तक : खुलासों ने उठाए बड़े सवाल

धान घोटाले की पूरी कहानी : दो महीने तक खुलती रहीं परतें, लेकिन जिम्मेदार अब भी बेपरवाह

जनवरी से फरवरी 2026 तक दैनिक 'घटती-घटना' की लगातार रिपोर्टिंग ने खोले कई राज,फिर भी सवाल कायम

ओंकार पाण्डेय

अंबिकापुर/सूरजपुर 15 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है,इसका काम केवल खबर छापना नहीं बल्कि सत्ता और व्यवस्था से जवाब मांगना भी है, सूरजपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों में सामने आए कथित घोटाले के मामले में जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान जो कुछ हुआ, वह पत्रकारिता और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों की एक बड़ी परीक्षा बन गया। इन दो महीनों के दौरान दैनिक 'घटती-घटना' ने लगातार कई खबरें प्रकाशित कीं, जिनमें धान खरीदी व्यवस्था में गंभीर अनियमितताओं,हजारों क्विंटल धान की कमी, रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक के अंतर,डिजिटल सिस्टम में गड़बड़ी और जांच के बावजूद कार्रवाई में ढिलाई जैसे मुद्दे सामने आए, इन खबरों की श्रृंखला ने पूरे जिले में हलचल मचा दी,लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने बड़े खुलासों के बाद भी जिम्मेदारी तय हो पाई? सूरजपुर जिले का धान खरीदी मामला केवल एक प्रशासनिक विवाद नहीं बल्कि जवाबदेही की बड़ी परीक्षा बन चुका है, दो महीने तक लगातार खबरें प्रकाशित हुई, कई तथ्य सामने आए और समाज में चर्चा भी हुई, अब यह प्रशासन और व्यवस्था पर निर्भर है कि वह इन सवालों का जवाब दे और दोषियों पर कार्रवाई करे, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना मीडिया का काम है और जवाब देना

पहला खुलासा : 7 जनवरी 2026

जनवरी की शुरुआत में प्रकाशित खबर ने पूरे मामले को सामने लाया,रिपोर्ट में कहा गया कि शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र में कागजों में 65 हजार क्विंटल धान दर्ज है,लेकिन वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं,इस खबर के सामने आने के बाद पहली बार लोगों को संदेह हुआ कि धान खरीदी व्यवस्था में कुछ बड़ा गड़बड़झाला हो सकता है।

दूसरी कड़ी : 10 जनवरी 2026

तीन दिन बाद प्रकाशित रिपोर्ट ने मामले को और गंभीर बना दिया,इस खबर में आरोप लगाया गया कि शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र में एक 'तिकड़ी' की भूमिका सामने आ रही है और पूरे सिस्टम में मिलीभगत की आशंका जताई गई,इस रिपोर्ट के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गई और जांच की मांग तेज हो गई।

तीसरी रिपोर्ट 12 जनवरी 2026

इस रिपोर्ट में सवाल उठाया गया–'जांच के बाद भी चुप्पी क्यों?' रिपोर्ट में बताया गया कि हजारों बोरी धान की कमी सामने आने के बावजूद प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है,यही वह मोड़ था जहां से यह मामला केवल एक खरीदी केंद्र की गड़बड़ी से आगे बढ़कर प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा बन गया।

15 जनवरी 2026: बड़ा आंकड़ा सामने

इस दिन प्रकाशित रिपोर्ट ने पूरे मामले को और बड़ा बना दिया,रिपोर्ट में कहा गया कि सूरजपुर जिले में धान खरीदी से जुड़े मामले में 52,908 बोरियों का अंतर सामने आया है और करीब 6.56 करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका जताई गई है,यह आंकड़ा सामने आते ही यह मामला केवल स्थानीय विवाद नहीं बल्कि एक बड़े आर्थिक घोटाले के रूप में देखा जाने लगा।

17 जनवरी 2026: जिम्मेदारी पर सवाल

एक और रिपोर्ट में यह कहा गया कि जांच में कमी पकड़ने के बावजूद वही लोग जिम्मेदार पदों पर बने हुए हैं, इस खबर में यह सवाल उठाया गया कि यदि जांच में गड़बड़ी सामने आई है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।

18 जनवरी 2026: खबर का असर

लगातार प्रकाशित खबरों के बाद प्रशासन हरकत में आया,रिपोर्ट के अनुसार धान खरीदी केंद्रों में अनियमितताओं को लेकर नोटिस जारी किए गए और जांच प्रक्रिया तेज करने की बात कही गई,हालांकि लोगों का कहना था कि यह कार्रवाई अभी भी पर्याप्त नहीं है।

23 जनवरी 2026: 11 करोड़ का मामला

जनवरी के अंत में प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया कि सूरजपुर जिले में धान खरीदी से जुड़े घोटाले का आंकड़ा 11 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है,इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई खरीदी केंद्रों में हजारों क्विंटल धान का अंतर सामने आया है।

25 जनवरी 2026: जमीन और संपत्ति का मामला

इस रिपोर्ट में एक और नया पहलू सामने आया, घोटाले से जुड़े लोगों के नाम पर 7.7 एकड़ जमीन सामने आने की चर्चा हुई, इस खबर ने मामले को और गंभीर बना दिया क्योंकि अब यह केवल धान खरीदी का मामला नहीं बल्कि संभावित आर्थिक नेटवर्क की ओर भी इशारा कर रहा था।

28 जनवरी 2026: सबसे बड़ा सवाल

जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित रिपोर्ट में पूछा गया— '13 हजार बोरियां कैसे गायब हुई और फिर कैसे पूरी हो गई?' इस खबर में दो अलग-अलग जांच और उनके अलग-अलग निष्कर्षों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए।

फरवरी 2026: जांच पर सवाल और तेज

जनवरी के बाद फरवरी में भी इस मामले पर लगातार खबरें प्रकाशित होती रहीं।

02 फरवरी 2026 इस दिन प्रकाशित रिपोर्ट में सवाल उठाया गया

'धान नहीं...घोटाला बोला गया?' रिपोर्ट में कहा गया कि जांच के बावजूद कई सवालों के जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं।

06 फरवरी 2026 इस रिपोर्ट का शीर्षक था...

'मगरमच्छ वाला घोटाला,कछुए वाली जांच' इसमें जांच प्रक्रिया की धीमी गति और प्रशासनिक उदासीनता पर व्यंग्य किया गया।

07 फरवरी 2026

इस दिन प्रकाशित रिपोर्ट में प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा सवाल उठाया गया और कहा गया 'खजाना जाए भाड़ में... पर घोटालेबाज सुरक्षित रहें' यह रिपोर्ट सिस्टम की जवाबदेही पर बड़ा सवाल बनकर सामने आई।

09 फरवरी 2026 इस रिपोर्ट में कहा गया...

'घोटाले,एफआईआर और वही जिम्मेदारी' यानी घोटाले की चर्चा, जांच और एफआईआर की बात तो हो रही है लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं हो रही।

10 फरवरी 2026

फरवरी की इस रिपोर्ट में तकनीकी सिस्टम पर सवाल उठाए गए, शीर्षक था— 'शून्य का जादू या सिस्टम का खेल?' इसमें डिजिटल रिकॉर्ड, एआई कैमरा और वास्तविक स्टॉक के बीच अंतर को लेकर संदेह जताया गया।

दो महीने की रिपोर्टिंग से निकले बड़े संकेत,जनवरी और फरवरी की सभी खबरों को जोड़कर देखें तो कुछ महत्वपूर्ण संकेत सामने आते हैं...

1. रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर- कई रिपोर्टों में यह सवाल उठाया गया कि रिकॉर्ड में दर्ज धान और वास्तविक भंडारण में अंतर क्यों दिख रहा है।
2. जांच की धीमी प्रक्रिया- लगातार रिपोर्टों में जांच की गति पर सवाल उठाए गए।
3. तकनीकी सिस्टम की भूमिका- एआई कैमरा, डिजिटल रिकॉर्ड और एसओपी के पालन को लेकर भी सवाल सामने आए।
4. प्रशासनिक जवाबदेही- सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि गड़बड़ी सामने आई है तो जिम्मेदारी किसकी है।

मीडिया ने निभाई जिम्मेदारी

इन दो महीनों के दौरान दैनिक 'घटती-घटना' ने लगातार इस मुद्दे को उठाया और कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने लाए, यह पत्रकारिता की उस भूमिका का उदाहरण है जिसमें मीडिया व्यवस्था से सवाल पूछता है और समाज को सच बताने का प्रयास करता है।

लेकिन जिम्मेदार कौन?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है इतनी खबरों,जांचों और चर्चाओं के बाद भी क्या जिम्मेदारी तय हुई? यदि नहीं,तो क्या यह मामला भी समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा?

जनकपुर काष्ठागार में लकड़ी का बड़ा खेल उजागर...150 की टीपी,ट्रक में निकली 208 लकड़ी,58 नग अतिरिक्त लकड़ी जब्त

संवादाता

जनकपुर (एमसीबी),16 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

एमसीबी जिले के जनकपुर वन परिक्षेत्र स्थित काष्ठागार (डिपो) में लकड़ी परिवहन के दौरान एक बड़ी अनियमितता सामने आई है,ट्रांजिट पास में दर्ज लकड़ी की संख्या और ट्रक में वास्तविक रूप से लोड लकड़ी के बीच भारी अंतर मिलने से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार डिपो से लकड़ी लेकर निकल रहे एक ट्रक को लेकर स्थानीय स्तर पर संदेह व्यक्त किया गया था, दस्तावेजों के अनुसार ट्रक में 150 नग लकड़ी दर्ज थी, लेकिन जब विरोध के बाद ट्रक को रोककर भौतिक सत्यापन किया गया तो उसमें से 208 नग लकड़ी बरामद हुई। यानी निर्धारित संख्या से 58 नग लकड़ी अतिरिक्त पाई गई,यह अंतर सामने आने के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया।

सजग कर्मचारियों ने रोका ट्रक- बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का खुलासा डिपो के कुछ कर्मचारियों की सजगता से संभव हो सका। ट्रक में लोड लकड़ी की संख्या को लेकर संदेह होने पर कर्मचारियों ने ट्रक को बाहर जाने से रोक दिया, स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों ने काष्ठागार के गेट पर ताला लगाकर ट्रक को रोक दिया और इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद ट्रक को खाली कराकर लकड़ियों की गिनती कराई गई,जब लकड़ियों की गिनती की गई तो दस्तावेजों और वास्तविक संख्या में भारी अंतर सामने आया।

दस्तावेजों में छेड़छाड़ की चर्चा- मामला उजागर होने के बाद यह भी चर्चा सामने आई कि विसंगति सामने आने के बाद सरकारी ट्रांजिट पास में सुधार या छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई,ताकि अंतर को छिपाया जा सके। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस पहलू की भी जांच की जानी चाहिए,यदि दस्तावेजों में छेड़छाड़ की बात सही साबित होती है तो यह मामला केवल लकड़ी की हेराफेरी का नहीं बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में हस्तक्षेप का भी गंभीर मामला बन सकता है।

अधिकारियों की भूमिका पर भी उठे सवाल- शुरुआती स्तर पर कुछ अधिकारियों द्वारा यह दावा किया गया था कि लकड़ी परिवहन में सब कुछ नियमों के अनुसार है, लेकिन जब मीडिया और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में लकड़ियों की गिनती हुई तो वास्तविकता सामने आ गई,सूत्रों के अनुसार संबंधित ठेकेदार ने भी ट्रक में अधिक लकड़ी होने की बात स्वीकार की है। इससे यह आशंका और गहरा गई है कि मामला केवल एक साधारण त्रुटि का नहीं बल्कि किसी बड़े खेल का हिस्सा हो सकता है।

प्रशासनिक चुप्पी से बढ़े संदेह- इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बावजूद अब तक संबंधित लोगों पर किसी बड़ी कार्रवाई की सूचना सामने नहीं आई है, इससे स्थानीय लोगों के बीच यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, वन विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकारी टीपी में दर्ज संख्या और वास्तविक लकड़ी की संख्या में इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया।

उठ रहे कई सवाल- इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, ट्रांजिट पास में दर्ज लकड़ी की संख्या और वास्तविक लोड में इतना अंतर कैसे

आया? क्या यह केवल मानवीय भूल है या इसके पीछे कोई संगठित तंत्र काम कर रहा है? दस्तावेजों में कथित छेड़छाड़ की कोशिश किसके निर्देश पर हुई? मामले को उजागर करने वाले कर्मचारियों पर दबाव क्यों बनाए जाने की चर्चा हो रही है?

निष्पक्ष जांच की मांग- जनकपुर काष्ठागार का यह मामला केवल 58 नग लकड़ी की अतिरिक्त बरामदगी का नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, क्षेत्र के नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इस मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके, फिलहाल यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की नजर अब प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

सुरक्षा के दावे फेल,छात्रावास में छात्र ने लगाई फांसी

व्यवस्था कटघरे में...

- आदिवासी छात्रों का भविष्य या भ्रष्टाचार की फैक्ट्री ? सोनहत की घटना से खुला राज
- आदिवासी छात्रावास या मौत का अड्डा ? सोनहत में छात्र की फांसी ने खोली व्यवस्था की पोल
- छात्रावास में लटक गया सपना : आदिवासी छात्र की मौत ने उठाए बड़े सवाल
- छात्रों के नाम पर पैसा,सुविधाओं में कटौती और अंत में मौत! सोनहत छात्रावास पर गंभीर सवाल
- सपनों के घर में मौत : आदिवासी छात्रावास की हकीकत आई सामने
- सुविधाओं की जगह सौदेबाजी ? छात्रावास में सीटों से लेकर सुविधाओं तक 'बोली' का खेल
- सरकारी योजना या गोरखधंधा ? आदिवासी छात्रावास पर उठे तीखे सवाल

आदिवासी छात्रावास योजना:उद्देश्य और वास्तविकता के बीच खाई

आदिवासी छात्रावास योजना को राज्य और केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना माना जाता है, इसका उद्देश्य दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी छात्रों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है, इन छात्रावासों के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आर्थिक रूप से कमजोर और दूरदराज के गांवों से आने वाले छात्र शिक्षा से वंचित न रहें,उन्हें सुरक्षित आवास,भोजन,पढ़ाई का वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकें,लेकिन जमीनी स्तर पर कई जगहों की स्थिति इस उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है,कई छात्रावासों में अव्यवस्था,लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं,सोनहत की घटना ने इस व्यवस्था के भीतर छिपे कई सवालों को फिर से उजागर कर दिया है।

प्रति छात्र मिलने वाली राशि में कथित बंदरबांट...

सूत्रों के अनुसार छात्रावास में रहने वाले प्रत्येक छात्र के लिए शासन द्वारा प्रतिमाह लगभग 1500 रुपये की राशि दी जाती है,यह राशि छात्रों के भोजन, नाश्ता,दूध, फल,स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए निर्धारित होती है,लेकिन आरोप है कि इस राशि का पूरा उपयोग छात्रों पर नहीं होता,सूत्र बताते हैं कि इस राशि का बड़ा हिस्सा ऊपर से नीचे तक आपसी तालमेल से बंट जाता है और छात्रों पर केवल औपचारिक खर्च किया जाता है,कई छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता और मात्रा को लेकर भी शिकायतें सामने आती रही हैं,छात्रों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाने की शिकायतें भी समय-समय पर सामने आती हैं,स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि प्रति छात्र मिलने वाली राशि का सही उपयोग किया जाए तो छात्रों को बेहतर भोजन और सुविधाएं मिल सकती हैं,लेकिन वर्तमान व्यवस्था में ऐसा होता हुआ कम ही दिखाई देता है।

आदिवासी छात्रों का भविष्य दांव पर

आदिवासी छात्रावास केवल एक आवासीय व्यवस्था नहीं हैं,बल्कि हजारों आदिवासी छात्रों के भविष्य का आधार हैं,इन छात्रावासों में रहने वाले अधिकांश छात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं, उनके परिवारों की उम्मीदें इस बात पर टिकी होती हैं कि उनका बच्चा पढ़-लिखकर बेहतर जीवन हासिल करेगा,लेकिन यदि छात्रावासों में अव्यवस्था,भ्रष्टाचार और असुरक्षा का माहौल बना रहेगा तो यह केवल छात्रों के वर्तमान ही नहीं बल्कि उनके भविष्य को भी प्रभावित करेगा।

व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता

सोनहत की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासी छात्रावास व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है,विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए, छात्रावासों की नियमित और पारदर्शी जांच,छात्रों को मिलने वाली राशि का पारदर्शी उपयोग,भोजन और सुविधाओं की गुणवत्ता की स्वतंत्र निगरानी,छात्र सुरक्षा के लिए सख्त नियम,शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था।

आखिर कब सुधरेगी व्यवस्था ?

सोनहत की यह घटना केवल एक जिले की समस्या नहीं है,यह उन सभी जगहों के लिए चेतावनी है जहां छात्रावास व्यवस्था कागजों में तो मजबूत दिखाई देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कमजोर साबित होती है, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह घटना भी कुछ दिनों की चर्चा बनकर रह जाएगी,या फिर इसके बाद वास्तव में व्यवस्था में सुधार की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाएंगे, यदि समय रहते सुधार नहीं किए गए,तो आदिवासी छात्रावासों का उद्देश्य ही सवालों के घेरे में आ जाएगा,और तब यह कहना गलत नहीं होगा कि जिन छात्रावासों को आदिवासी छात्रों के सपनों को पंख देने के लिए बनाया गया था, वही कहीं उनके सपनों का सबसे बड़ा बोझ न बन जाए।

छात्रावास में व्यवस्था का फंदा या आत्महत्या का सच ?
सोनहत के आदिवासी छात्र की मौत ने खोल दी सिस्टम की परतें

-राजन पाण्डेय-

सोनहत (कोरिया),16 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड में स्थित एक आदिवासी छात्रावास से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है, छात्रावास में रह रहे एक आदिवासी छात्र ने वहीं फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, यह घटना केवल एक छात्र की मौत नहीं है,बल्कि

उस पूरी व्यवस्था की सच्चाई को उजागर करती है जिसे आदिवासी छात्रों के भविष्य को संवारने के उद्देश्य से बनाया गया था।

जिस स्थान को शिक्षा, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य का आधार माना जाता है,वहीं यदि एक छात्र को इतना मानसिक दबाव या असुरक्षा महसूस हो कि वह अपनी जीवनलीला समाप्त कर ले, तो यह केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि प्रशासनिक और संस्थागत विफलता का प्रतीक बन जाती है,सोनहत की इस घटना ने एक बार फिर आदिवासी छात्रावासों की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक निगरानी, वित्तीय पारदर्शिता और छात्र सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

जिम्मेदारी तय करना क्यों मुश्किल हो जाता है ?

ऐसे मामलों में अक्सर यह देखा गया है कि जब कोई बड़ी घटना सामने आती है तो निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी जाती है,लापरवाही,कर्तव्य में चूक या अन्य आरोप लगाकर अधीक्षक या अन्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि छात्रावास व्यवस्था की खराब स्थिति के लिए केवल निचले कर्मचारी ही जिम्मेदार नहीं होते,ऊपर के स्तर पर बैठे अधिकारी,जिनकी जिम्मेदारी निरीक्षण और निगरानी की होती है,अक्सर कार्रवाई के दायरे से बाहर रह जाते हैं,इस कारण व्यवस्था में जवाबदेही का अभाव बना रहता है और समस्याएं बार-बार दोहराई जाती हैं।

सहायक आयुक्त के कार्यकाल पर भी उठ रहे सवाल

जिले में वर्तमान में कार्यरत सहायक आयुक्त के कार्यकाल को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं,कई लोगों का कहना है कि इस दौरान छात्रावासों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ,कुछ मामलों में छात्रों को अपनी समस्याओं को लेकर मीडिया के सामने आने तक की नौबत आ गई, अब सोनहत की घटना ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है,लोगों का मानना है कि यदि समय रहते व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जाती तो शायद ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था।

छात्र की मौत और परिजनों के आरोप

जिस छात्र ने छात्रावास में फांसी लगाई,उसके परिजनों ने छात्रावास के अधीक्षक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं,परिजनों का कहना है कि छात्र पर किसी मामले को लेकर दोनों का दबाव था और वह मानसिक रूप से परेशान था,बताया जाता है कि जिस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की रात्रिकालीन ड्यूटी थी, वह पहले भी छात्र सुरक्षा से जुड़े एक मामले में जेल जा चुका है और हाल ही में उस मामले से बरी हुआ है,ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि छात्र सुरक्षा से जुड़े विवादित व्यक्ति को फिर से ऐसी जिम्मेदारी क्यों दी गई।

निरीक्षण व्यवस्था : कागजों तक सीमित ?

छात्रावासों की निगरानी के लिए कई स्तरों पर निरीक्षण की व्यवस्था बनाई गई है,इनमें शामिल हैं विकासखंड स्तर पर निरीक्षण, जिला स्तर पर निगरानी,राज्य स्तर पर समय-समय पर जांच लेकिन यदि इन सब व्यवस्थाओं के बावजूद छात्रावासों की स्थिति में सुधार नहीं होता,तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या निरीक्षण वास्तव में प्रभावी तरीके से किया जा रहा है या केवल कागजों में दर्ज होकर रह जाता है।

अतिरिक्त सीटों के नाम पर कमाई का खेल

छात्रावासों में एक और बड़ा आरोप सामने आता है स्वीकृत सीटों से अधिक छात्रों को दर्ज करने का खेल,सूत्रों के अनुसार कई जगहों पर छात्रावास की क्षमता से अधिक छात्रों को दर्ज किया जाता है,इसके लिए अंदरखाने बोली लगने की भी चर्चा होती है,बताया जाता है कि जो व्यक्ति अधिक बोली लगाने को तैयार होता है, उसे अतिरिक्त छात्रों को रखने का अवसर मिल जाता है,इसके बाद इन अतिरिक्त छात्रों के नाम पर मिलने वाली सुविधाओं और राशि का उपयोग भी कथित तौर पर कमाई के साधन के रूप में किया जाता है,कुछ मामलों में अभिभावकों से भी पैसे लेने की बात सामने आती है,जब तक छात्र की सीट की औपचारिक स्वीकृति नहीं मिलती,तब तक अभिभावकों से खुराकी या अन्य मदों के नाम पर राशि ली जाती है,यह स्थिति उन गरीब आदिवासी परिवारों के लिए और भी कठिन हो जाती है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले ही आर्थिक संघर्ष कर रहे होते हैं।

चयन प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में...

छात्रावासों में छात्रों के चयन के लिए एक चयन समिति बनाई जाती है, इस समिति की बैठक में छात्रों का चयन किया जाना चाहिए,लेकिन सूत्रों का कहना है कि कई मामलों में यह प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है,चयन पहले से तय होता है और समिति की बैठक केवल कागजी खानापूर्ति के रूप में की जाती है,कुछ मामलों में यह भी आरोप है कि चयन समिति की बैठक जानबूझकर देर से आयोजित की जाती है ताकि अतिरिक्त छात्रों के नाम पर वसूली का खेल जारी रह सके,इस कारण पूरी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठते रहे हैं।

हर साल सामने आती हैं छात्रावास से जुड़ी घटनाएं

कोरिया जिले के छात्रावासों का यदि रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग हर वर्ष किसी न किसी छात्रावास से विवाद, अव्यवस्था या लापरवाही से जुड़ी खबर सामने आती रही है,कभी भोजन व्यवस्था को लेकर विवाद सामने आते हैं,तो कभी छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन को लेकर शिकायतें होती हैं, कई बार छात्र स्वयं मीडिया या सामाजिक संगठनों के माध्यम से अपनी समस्याओं को सामने लाते हैं, इसके बावजूद व्यवस्था में ठोस सुधार देखने को नहीं मिलता,कई जानकार इसे प्रशासनिक उदासीनता और जवाबदेही की कमी का परिणाम मानते हैं।

सरिया बिक्री की रकम से खरीदे गए तीन ट्रक जब्त,कुल कीमत लगभग 1.50 करोड़

-संवाददाता-

सूरजपुर,16 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

अमानत में खयानत के एक बड़े मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने में सूरजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है,पुलिस टीम ने उत्तरप्रदेश में दबिश देकर लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, इससे पहले इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सरिया बिक्री से खरीदे गए तीन ट्रकों को भी जब्त किया गया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपये बताई जा रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 14 जनवरी 2026 को ग्राम नयनपुर निवासी अमित पाण्डेय ने थाना सूरजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके यू.बी. वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड प्लांट नयनपुर से ट्रक क्रमांक P 61 AT 2832 के चालक राहुल सिंह यादव को लगभग 30 टन 160 किलो सरिया (छड़) लोड कर भदौरी, उत्तरप्रदेश भेजा गया था, लेकिन आरोपी चालक ने विश्वासघात करते हुए सरिया को गंतव्य तक न पहुंचाकर बेईमानीपूर्वक हड़प लिया। गायब किए गए सरिया की कीमत करीब 15 लाख 23 हजार 908 रुपये बताई गई, प्रार्थी की शिकायत पर थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 23/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

उत्तरप्रदेश में दबिश देकर पकड़ा गया आरोपी- मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम गठित की थी, पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले के

विंध्याचल क्षेत्र में दबिश दी और फरार आरोपी सुनील विश्वकर्मा (28 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ग्राम बहुर, थाना सिंगरामऊ, जिला जौनपुर (उत्तरप्रदेश) का निवासी है, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद 16 मार्च 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका- इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी और सीएसपी बेनार्ड कुजूर के मार्गदर्शन में थाना सूरजपुर पुलिस की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कार्रवाई में थाना प्रभारी विमलेश दुबे,एएसआई देवनाथ चौधरी, आरक्षक जितेन्द्र पटेल और चन्द्रप्रकाश साहू सक्रिय रूप से शामिल रहे,पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है और आवश्यकता पड़ने पर आगे और कार्रवाई की जाएगी।

पहले तीन आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने 1 फरवरी 2026 को इस मामले में शामिल मनीष यादव, सूरज सोनी और मनीष सिंह परिहार को गिरफ्तार किया था, पूछताछ में सामने आया कि सरिया बेचकर मिली रकम से आरोपियों ने ट्रक खरीदे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन ट्रकों को जब्त किया,जिनकी कुल कीमत लगभग 1.50 करोड़ रुपये आंकी गई है,हालांकि इस पूरे मामले में एक अन्य आरोपी सुनील विश्वकर्मा फरार चल रहा था,जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी।

नाम सुधार सूचना

मैं दीपक कुमार राजवाड़े आ. चंदर राजवाड़े उम्र 32 वर्ष, निवासी वार्ड नं-42 नवागढ़ अम्बिकापुर थाना व तह0 अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. । यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं-7870 2117 0951 में उसका नाम भुलवश रेशमी राजवाड़े दर्ज है। जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र क्र- 85 में मेरी पुत्री का उषा राजवाड़े नाम दर्ज है,जो सही है । मेरी पुत्री के आधार कार्ड में अंकित नाम रेशमी को विलोपित कर जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उषा राजवाड़े दर्ज कराना चाहता हूं तथा मेरी पुत्री के आधार कार्ड में नाम सुधारने के संबंध में रात्रपत्र जारी कराना चाहता हूं, तथा मुझे शासन के समस्त नियम एवं शर्तें मान्य हैं। मेरी पुत्री के नाम समर्थन में रात्रपत्र जारी कराने हेतु स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

सपथकर्ता
दीपक कुमार राजवाडे

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला-सूरजपुर,छ0ग0

ईश्तहार

एतद द्वारा आम ग्रामीण जन ग्राम पंचायत क्षेत्र मानपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक अली अहमद आ0 अमानउल्ला जाति मुसलमान निवासी गोपालपुर तहसील सूरजपुर के द्वारा ग्राम गोपालपुर मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 716/2, 717/4, 730/1, 730/2 कुल रकबा 1.41 हे. भूमि पर खातेदार की मृत्यु हो जाने के कारण उनका नाम विलोपित कर आवेदक अपना नाम दर्ज कराये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

अतः उक्त सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 06.04.2026 को न्यायालयीन समयावधि में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति पेश कर सकते हैं। उसके पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 12.03.2026 को न्यायालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील — तहसीलदार ,सूरजपुर,जिला-सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला-सूरजपुर,छ0ग0

ईश्तहार

एतद द्वारा आम ग्रामीण जन ग्राम पंचायत क्षेत्र मानपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक यशमीता खातून पति अजहर जाति मुसलमान निवासी सूरजपुर के द्वारा सूरजपुर मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 155/10, 727, 728 कुल रकबा 0.3840 हे. पर खातेदार की मृत्यु हो जाने के कारण फौति नामान्तरण कराये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

अतः उक्त सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 06.04.2026 को न्यायालयीन समयावधि में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति पेश कर सकते हैं। उसके पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 12.03.2026 को न्यायालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

सील — तहसीलदार ,सूरजपुर,जिला-सूरजपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी सूरजपुर जिला-सूरजपुर,छ0ग0

रा0प्र0क्र0 /अ-20(1)/25-26

ईश्तहार

आगामी तिथि 17/4/2026 इस सार्वजनिक ईश्तहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता/संस्था/विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है आवेदक ताराचंद नाहटा आ0 स्व. किशनलाल नाहटा उम्र लगभग 68 वर्ष निवासी मेन रोड सूरजपुर थाना व तहसील सूरजपुर जिला- सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व व अधिपत्य की नजूल भूमि प्लाट नम्बर 2132/2 रकबा क्रमशः 2541 वर्गफीट भूमि का लीज दिनांक 31/03/2026 को समाप्त होने से आगामी 30 वर्ष के लिए लीज नवीनीकरण कराये जाने हेतु अनुरोध मा. न्यायालय अपर कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष किया गया है। जो अग्रिम कार्यवाही हेतु एतद् न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन लंबित है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति / संस्था/विभाग को कोई दावा/आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक / लीगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा/ आपत्ति दिनांक 17/4/2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 16/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील — नजूल अधिकारी ,सूरजपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी सूरजपुर जिला-सूरजपुर,छ0ग0

रा0प्र0क्र0

ईश्तहार

आगामी तिथि0 02/04/2026 इस सार्वजनिक ईश्तहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता/संस्था/विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक दिलीप कुमार सोनी आ0 स्व. विजय कुमार सोनी, उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी वार्ड क्र 16 मेन रोड सूरजपुर तहसील व जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदक के पिता स्व. विजय कुमार सोनी आ0 हजारी लाल सोनी के नाम पर ग्राम सूरजपुर में नजूल भूमि प्लाट नम्बर 2130/2, 2131/5 कुल रकबा 0.09 (4335) वर्गफुट भूमि स्थित है। स्व. विजय कुमार सोनी की मृत्यु दिनांक 28/01/2022 को हो जाने से उनका नाम विलोपित कर वंशवृक्ष अनुसार फौती नामांतरण दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। जो इस न्यायालय में विचाराधीन लंबित है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग को कोई दावा/आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक/लीगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा/आपत्ति दिनांक 2/4/2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 12/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया ।

सील — नजूल अधिकारी ,सूरजपुर

CMYK

एक ही न्यायालय,दो आदेश...

पहले कब्जा हटाने का आदेश, बाद में अतिक्रमण ही नहीं...

भांडी के कर्मा चौक मामले में अतिक्रमण से अनापत्ति तक का रहस्यमय सफर

पहले कब्जा हटाने का आदेश, बाद में अतिक्रमण ही नहीं...तहसीलदार न्यायालय के दो फैसलों से उठे कई सवाल

पहले अतिक्रमण हटाओ,फिर कोई अतिक्रमण नहीं : भांडी के कर्मा चौक पर आदेशों का उलटफेर

नहर की जमीन पर चौक या फाइलों का खेल? एक ही अदालत के दो फैसलों ने बढ़ाए सवाल

20 दिन में हटाओ कब्जा...फिर

मामला खत्म : भांडी में आदेशों का रहस्यमय यू-टर्न

अतिक्रमण से अनापत्ति तकः भांडी के कर्मा चौक ने खोली प्रशासनिक विरोधाभास की परतें

नहर वही, चौक वही... बस आदेश बदल गए!

एक ही अदालत,दो आदेशः भांडी के कर्मा चौक मामले में प्रशासनिक पहेली

कागजों में बदली नहर की सीमा? कर्मा चौक मामले में फैसलों पर उठे बड़े सवाल

रवि सिंह

कोरिया,16 मार्च 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र के ग्राम भांडी में बने भक्त माता कर्मा चौक को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है,जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं,हैरानी की बात यह है कि एक ही न्यायालय से एक ही प्रकरण में दो अलग-अलग आदेश सामने आए हैं, पहले आदेश में जहां निर्माण को नहर की भूमि पर अतिक्रमण बताते हुए कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए,वहीं बाद के आदेश में उसी निर्माण को अतिक्रमण की श्रेणी से बाहर बताते हुए मामला समाप्त कर दिया गया, यह विरोधाभास अब स्थानीय स्तर पर चर्चा और सवालों का विषय बन गया है।

कोरिया में 'नया नियम'? नहर की जमीन पर कब्जे को भी मिल सकती है NOC
पहले बताया अतिक्रमण,अब दे दी अनापत्तिः कोरिया में नहर भूमि विवाद पर बड़ा खुलासा
नहर की जमीन पर एनओसी! कोरिया में नियमों को ठेंगा,जल अधिनियम पर बड़ा सवाल
अतिक्रमण हटाने की जगह मिला प्रमाण पत्र! जल संसाधन विभाग की भूमिका पर सवाल
नहर की सरकारी जमीन पर कब्जा और अब अनापत्ति प्रमाण पत्र! प्रशासन कटघरे में...

नहर पर बना चौक या फाइलों का खेल?
2023 में अतिक्रमण, 2026 में 'नो ऑब्जेक्शन'
2023 : अतिक्रमण हटाने की सिफारिश
फाइलों की दुनिया का 'चमत्कार'
स्थानीय चर्चा और सवाल
तीन साल में क्या बदल गया?
कोरिया में 'नया नियम'? नहर की जमीन

क्या है मामला ...

ग्राम भांडी में खसरा नंबर 101/15 की भूमि पर भक्त माता कर्मा चौक का निर्माण किया गया,चौक के बीच में माता कर्मा की मूर्ति स्थापित की गई और चारों ओर लगभग सात फीट ऊंची दीवार बनाकर चबूतरा तैयार किया गया,निर्माण क्षेत्र करीब 290 से 338 वर्गफुट बताया गया,यह स्थल साहू समाज की आस्था से जुड़ा बताया जाता है,क्योंकि माता कर्मा को साहू समाज की आराध्य देवी माना जाता है,लेकिन यह धार्मिक स्थल जल्द ही नहर भूमि पर अतिक्रमण के विवाद में बदल गया।

पहला आदेश : अतिक्रमण मानकर हटाने के निर्देश...

तहसीलदार न्यायालय,बैकुंठपुर के पहले आदेश में जांच के आधार पर कहा गया कि निर्माण जल संसाधन विभाग की माइनर नहर की भूमि पर किया गया है, आदेश में उल्लेख किया गया कि लगभग 29×10 फुट क्षेत्र में 7.5 फीट ऊंची कंक्रीट दीवार बनाकर मूर्ति स्थापित की गई,जो नहर की भूमि के भीतर आती है,इस आधार पर न्यायालय ने इसे छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत अतिक्रमण मानते हुए संबंधित पक्ष को 20 दिनों के भीतर कब्जा हटाने का आदेश दिया।

फिर बदली कहानी...

मामले में आगे चलकर एक नया मोड़ आया, इस बार जल संसाधन विभाग की ओर से जारी एक पत्र सामने आया जिसमें कहा गया कि निर्माण से नहर को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है और कोई अतिक्रमण नहीं किया गया,यानी जिस निर्माण को पहले नहर की जमीन पर बताया गया था,उसी निर्माण को विभाग ने बाद में बिना आपत्ति का निर्माण बता दिया।

दूसरा आदेश : मामला समाप्त

नई विभागीय रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में फिर सुनवाई हुई, इस बार आदेश में कहा गया कि जल संसाधन विभाग के अनुसार निर्माण से नहर को कोई नुकसान नहीं हुआ,पंचायत का प्रस्ताव और सरकारी स्वीकृति मौजूद है,इसलिए यह निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता,इसी आधार पर न्यायालय ने प्रकरण को समाप्त करते हुए केस को दाखिल-दफ्तर कर दिया,पर सवाल है की सरकारी स्वीकृति की जमीन की थी? क्या न्यायालय ने पूछा या न्यायालय ने छुपाया?

सवालों का पहाड़

अब इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ही निर्माण को पहले अतिक्रमण कैसे माना गया? और बाद में वही निर्माण अतिक्रमण नहीं कैसे हो गया? क्या शुरुआती जांच गलत थी? या बाद में विभागीय रिपोर्ट बदलने से स्थिति बदल गई?

फाइलों का यू-टर्न

इस मामले को देखने वाले कई लोग इसे सरकारी फाइलों के यू-टर्न का उदाहरण बता रहे हैं,क्योंकि पहले आदेश में अतिक्रमण हटाने के निर्देश और बाद के आदेश में अतिक्रमण ही नहीं,अगर व्यंग्य में कहा जाए तो ऐसा लगता है जैसे नहर अपनी जगह से नहीं हटी,लेकिन कागजों में उसकी सीमा बदल गई।

नियम क्या कहते हैं...

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार माइनर नहर,उसकी पटरी और आसपास का क्षेत्र सामान्यतः सरकारी संपत्ति माना जाता है,नहर के दोनों किनारों पर एक सुरक्षा क्षेत्र रखा जाता है ताकि मरम्मत और रखरखाव का काम किया जा सके,ऐसे में बिना अनुमति निर्माण को सामान्यत : अतिक्रमण माना जाता है,हालांकि कुछ मामलों में विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है,लेकिन यह आमतौर पर पुल,पाइपलाइन या सड़क क्रॉसिंग जैसे सार्वजनिक कार्यों के लिए होता है,निजी या स्थायी निर्माण सामान्यतः अनुमति योग्य नहीं माने जाते।

सामाजिक और राजनीतिक चर्चा

इस मामले में एक और पहलू भी चर्चा में है। माता कर्मा साहू समाज की आराध्य देवी मानी जाती हैं और क्षेत्र में समाज का प्रभाव भी है, कुछ लोग मानते हैं कि इस पूरे मामले में सामाजिक दबाव और स्थानीय समीकरण भी भूमिका निभा सकते हैं,हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।

अंत में...

भांडी का भक्त माता कर्मा चौक आज भी उसी स्थान पर खड़ा है, नहर भी वहीं बह रही है और गांव का जीवन भी सामान्य है,लेकिन सरकारी दस्तावेजों में दर्ज इस पूरे घटनाक्रम ने यह जरूर दिखा दिया है कि प्रशासनिक व्यवस्था में एक ही मामले की कहानी समय के साथ बदल भी सकती है, कभी वह अतिक्रमण बन जाती है,और कभी अनापत्ति, और जब ऐसा होता है तो सवाल भी उतने ही बड़े खड़े हो जाते हैं।

असली मामला क्या दिख रहा है,तीनों पत्रों को साथ देखें तो बड़ा विरोधाभास दिखता हैः

साल	विभाग का बयान
2023	नहर की जमीन पर अतिक्रमण
2023	अतिक्रमण हटाने की सिफारिश
2026	कोई अतिक्रमण नहीं

यानी पहले अवैध बताया गया, बाद में वैध बताया जा रहा है।

तीनों दस्तावेज़ जल संसाधन विभाग,बैकुंठपुर (जिला कोरिया,छत्तीसगढ़) के आधिकारिक पत्र हैं

पहला दस्तावेज़ (दिनांक 12/06/2023)- इस पत्र में लिखा है कि ग्राम भांडी में भक्त माता कर्मा चौक का निर्माण किया गया है और जांच में पाया गया कि सिलफोडा जलाशय की माइनर नहर की जमीन पर 29×10 = 290 वर्गफुट में 7.5 फीट ऊंची कंक्रीट दीवार बनाकर निर्माण किया गया, बीच में कर्मा माता की मूर्ति स्थापित की गई, नहर की चौड़ाई 32 फीट बताई गई, इसलिए लिखा गया कि यह निर्माण नहर की सीमा के अंदर है, इस पत्र में साफ कहा गया कि अतिक्रमण है और NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) नहीं दिया जा सकता।

दूसरा दस्तावेज़ (दिनांक 06/07/ 2023)- इस पत्र में लिखा है की निरीक्षण किया गया माइनर नहर की जमीन पर निर्माण किया गया है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया,यह पत्र भी मानता है कि निर्माण नहर की जमीन पर है और हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए।

तीसरा दस्तावेज़ (दिनांक 06/02/2026)- यह सबसे नया पत्र है,इसमें लिखा गया की ग्राम भांडी में कर्मा चौक बनाया गया है, उसके पीछे माइनर नहर गुजरती है, निर्माण से नहर को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई अतिक्रमण नहीं किया गया,विभाग को कोई आपत्ति नहीं,इस पत्र में पूरी तरह उल्टा लिखा गया – कि कोई अतिक्रमण नहीं है।

ड्रोन ने खोली जंगल की भट्ठी,जिले की नींद क्यों नहीं टूटी?

सरगुज़ा उड़नदस्ता की कार्रवाई से खुला महुआ शराब का बड़ा खेल, कोरिया पुलिस और आबकारी पर उठे सवाल

क्या पुलिस को भी अब ड्रोन टीम की जरूरत?

गदबदी जंगल में अवैध महुआ शराब के बड़े नेटवर्क का खुलासा जिस तरह आबकारी उड़नदस्ता ने ड्रोन कैमरे की मदद से किया,उसने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। आज लगभग हर जिले की पुलिस के पास साइबर सेल या साइबर टीम मौजूद है,जो तकनीक के माध्यम से अपराध की जानकारी जुटाने और जांच करने का काम करती है,लेकिन इस कार्रवाई ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या केवल साइबर टीम ही पर्याप्त है,या अब पुलिस को भी ड्रोन तकनीक से लैस विशेष टीम की जरूरत पड़ेगी? जंगल और दुर्गम क्षेत्रों में चल रहे अवैध कारोबार–जैसे शराब निर्माण, लकड़ी तस्करी या अन्य गतिविधियों–की निगरानी जमीन से करना मुश्किल होता है, ऐसे में ड्रोन कैमरा अपराधियों की गतिविधियों को पकड़ने में कारगर साबित हो सकता है, गदबदी जंगल की कार्रवाई ने यह दिखा दिया कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से छिपे हुए अवैध कारोबार का भी आसानी से पता लगाया जा सकता है,अब सवाल यह है कि क्या पुलिस विभाग भी भविष्य में साइबर टीम के साथ ड्रोन तकनीक को अपनाकर अपनी कार्रवाई को और हाईटेक बनाएगा, ताकि दूरदराज और जंगल क्षेत्रों में भी प्रभावी कार्रवाई संभव हो सके।

ड्रोन कैमरे से जंगल में छापेमारी

संभागीय आबकारी उड़नदस्ता सरगुजा की टीम ने 15 मार्च को हाईटेक तरीके से कार्रवाई करते हुए गदबदी जंगल में छापा मारा, सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने पहले ड्रोन कैमरे की मदद से जंगल में गतिविधियों की निगरानी की,सूत्रों के अनुसार यह इलाका इतना घना है कि जब भी कोई टीम एक दिशा से पहुंचती है तो आरोपी दूसरी दिशा से जंगल के रास्ते भाग जाते हैं,इसी वजह से इस बार ड्रोन कैमरे से पहले पूरे इलाके की लोकेशन और गतिविधियों की निगरानी की गई, उसके बाद टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर कार्रवाई की।

-संवाददाता-

बैकुंठपुर/कोरिया,16 मार्च 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के गदबदी-फाटपानी के घने जंगल में लंबे समय से महुआ शराब बनाने और सप्लाई करने का धंधा चल रहा था,स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं थी,जंगल के भीतर बड़े पैमाने पर महुआ शराब बनाई जाती थी और फिर जिले भर में इसकी सप्लाई होती थी,लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस अवैध कारोबार पर कार्रवाई कोरिया जिले की पुलिस या स्थानीय आबकारी अमले ने नहीं,बल्कि सरगुजा संभाग के आबकारी उड़नदस्ता ने की,और वह भी ड्रोन कैमरे की मदद से,अब इस कार्रवाई के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है,क्या जिले की पुलिस और आबकारी विभाग को इस अवैध कारोबार की जानकारी नहीं थी?

ड्रोन से खुला राज,अब हाईटेक बनाम पारंपरिक सिस्टम की चर्चा

इस कार्रवाई की एक खास बात यह भी रही कि ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर पहली बार जंगल में अवैध शराब निर्माण का खुलासा किया गया,अब चर्चा यह भी शुरू हो गई है कि क्या संभागीय उड़नदस्ता स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग से ज्यादा हाईटेक हो गया है? क्योंकि जिस जंगल में वर्षों से अवैध शराब बन रही थी, उसका खुलासा आखिर ड्रोन कैमरे ने कर दिया।

कार्रवाई सराहनीय,लेकिन सवाल भी जरूरी

गदबदी जंगल में हुई इस कार्रवाई ने एक तरफ जहां अवैध शराब के कारोबार का खुलासा किया है,वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, अब लोगों के बीच चर्चा यही है कि अगर ड्रोन कैमरा जंगल में छिपी भट्ठियों को ढूंढ सकता है,तो क्या स्थानीय सिस्टम को यह सब दिखाई नहीं देता था? कार्रवाई तो हो गई,लेकिन इस कार्रवाई ने जिले की जिम्मेदार एजेंसियों की सक्रियता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न भी लगा दिया है।

दो आरोपी गिरफ्तार,भारी मात्रा में महुआ शराब और लाहन जब्त

कार्रवाई के दौरान आबकारी टीम ने कोरिया जिले के कथित मुख्य सप्लायर नीलकमल सिंह उर्फ नीलू सिंह और उसके साथी संतोष बरगाह को गिरफ्तार किया,दोनों आरोपी फाटपानी गदबदी क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं और अपने घर के नीचे जंगल के नाले के पास बड़े पैमाने पर महुआ शराब बनाकर सप्लाई करते थे,छापेमारी में 55 लीटर महुआ शराब, 3500 किलोग्राम महुआ लाहन,तथा 25 लीटर तैयार महुआ शराब जब्त की गई, दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1),34(2) और 59(क) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय बैकुंठपुर में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

स्थानीय लोगों की सूचना,बाहर की टीम की कार्रवाई

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि लंबे समय से कोरिया जिले के लोगों द्वारा उन्हें फोन पर सूचना दी जा रही थी कि गदबदी जंगल में बड़े पैमाने पर महुआ शराब बनाकर पूरे जिले में सप्लाई की जा रही है, उन्होंने बताया कि जंगल क्षेत्र में कार्रवाई करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि आरोपी पहले ही भाग जाते हैं,इसलिए इस बार पूरी योजना बनाकर ड्रोन कैमरे की मदद से कार्रवाई की गई।

सबसे बड़ा सवालः जिले की जिम्मेदार एजेंसियां कहां थीं?

कार्रवाई भले ही सराहनीय हो,लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं,क्योंकि जिस अवैध शराब कारोबार की जानकारी संभागीय उड़नदस्ता को मिल सकती है,उसकी जानकारी जिले के पुलिस और आबकारी अमले को क्यों नहीं मिली? स्थानीय लोगों का कहना है कि गदबदी जंगल में यह धंधा लंबे समय से चल रहा था,ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? या जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई?

कार्यवाही में इनकी रही भूमिका

इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता,आबकारी उपनिरीक्षक टी.आर. केहरी,मुख्य आरक्षक कुमारू राम,रमेश दुबे,अशोक सोनी,नगर सैनिक गणेश पांडेय,रणविजय सिंह,ओमप्रकाश गुप्ता,महिला सैनिक राजकुमारी सिंह और चंद्रावती की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

संघर्ष,ट्रॉमा-रिजेक्शन से उठकर स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस बनीं...स्कूल में बुलिंग होती थी,तभी सोचा कि एक दिन सबको कुछ बनकर दिखाऊंगी : भूमि पेडनेकर

संघर्ष,ट्रॉमा,रिजेक्शन और सामाजिक तानों के बीच खुद को साबित करने वाली अभिनेत्री का नाम है भूमि पेडनेकर। मुंबई की चमकदार फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाना आसान नहीं होता,खासकर तब जब शुरुआत आत्म-संदेह,असुरक्षा और निजी आघातों से भरी हो। स्कूल के दिनों में बुलिंग का सामना करने वाली भूमि को उनके वजन और लुक्स को लेकर ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन उन्होंने इन्हीं अनुभवों को अपनी ताकत बना लिया। 14 साल की उम्र में छेड़छाड़ की घटना और 18 वर्ष की उम्र में पिता के निधन ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया,पर टूटने के बजाय उन्होंने जिम्मेदारी उठाई और खुद को मजबूत बनाया। फिल्मी सफर भी आसान नहीं रहा। पारंपरिक हीरोइन जैसे लुक्स न होने की वजह से उन्हें कई ऑडिशन में रिजेक्शन झेलना पड़ा। यहां तक कि एक्टिंग कोर्स से निकाले जाने का झटका भी लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करते हुए उन्होंने सिनेमा को करीब से समझा और फिर 'दम लगा के हईशा' से ऐसा डेब्यू किया जिसने उन्हें रातोंरात गंभीर अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। 30 किलो वजन बढ़ाने का साहसिक फैसला हो या बाद में फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन, भूमि ने हर चुनौती को स्वीकार किया। आज वह कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा की मजबूत और भरोसेमंद आवाज बन चुकी हैं।

भूमि पेडनेकर का जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि

भूमि पेडनेकर का जन्म 18 जुलाई 1989 को मुंबई में हुआ। वे एक शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता सतीश पेडनेकर महाराष्ट्र सरकार में होम और लेबर मिनिस्टर रह चुके थे, जबकि उनकी मां सुमित्रा हुड्डा पेडनेकर सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं। भूमि की एक बहन भी हैं,समीक्षा पेडनेकर,जो वकालत के पेशे में हैं।

स्कूल के दिन और बुलिंग का अनुभव

भूमि ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के आर्य विद्या मंदिर स्कूल, जुहू से पूरी की। स्कूल के दिनों में उन्हें बुलिंग का सामना भी करना पड़ा। कभी उनके वजन को लेकर टिप्पणी की जाती, तो कभी उनके लुक्स पर तंज कसा जाता। भूमि कहती हैं कि जब स्कूल में बुलिंग होती थी, तो घर आकर उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता था। उनका आत्मविश्वास कभी नहीं टूटा। वे बताती हैं कि जब भी स्टेज पर जाती थीं, तो उन्हीं बुलीज को देखती थीं और मन में ठान लेती थीं कि एक दिन खुद को साबित करके दिखाएंगी। यहीं से उनके भीतर अभिनेत्री बनने का सपना और मजबूत हुआ।

14 साल की उम्र में छेड़छाड़ की घटना, भीतर तक हिला देने वाला अनुभव

भूमि का बचपन आम दिखने वाला जरूर था, लेकिन भीतर कई अनकहे संघर्ष थे। 14 साल की उम्र में बांद्रा के एक मेले में उनके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। यह अनुभव उनके लिए गहरा मानसिक आघात लेकर आया। भूमि कहती हैं कि उस घटना ने उन्हें भीतर तक हिला दिया था और लंबे समय तक वे असुरक्षित महसूस करती रहीं।

18 की उम्र में पिता का निधन, अचानक संभाली परिवार की जिम्मेदारी

जब भूमि 18 वर्ष की थीं, तभी उनके पिता का निधन हो गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा भावनात्मक झटका था। पिता उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम थे। अचानक परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई।

हीरोइन जैसे लुक पर सवाल, ऑडिशन में लगातार झेलना पड़ा रिजेक्शन

इस घटना ने उन्हें भीतर से परिपक्व बना दिया। उन्होंने तय किया कि वे खुद को कमजोर नहीं पड़ने देंगी। यही वह मोड़ था, जब उन्होंने करियर को गंभीरता से लेना शुरू किया। भूमि बचपन से ही अभिनय की ओर आकर्षित थीं। वे सिनेमा और थिएटर से बेहद प्रभावित थीं। किशोरावस्था में ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ही करियर बनाना है।

व्हिस्टलिंग वुड्स इंटरनेशनल से निकाली गई,लेकिन सपनों से नहीं टूटीं

लेकिन शुरुआत आसान नहीं रही। उन्होंने ऑडिशन दिए, लेकिन कई बार रिजेक्ट हुईं। उन्हें बताया जाता था कि वे पारंपरिक हीरोइन जैसी नहीं दिखतीं। इंडस्ट्री में जहां एक खास तरह की खूबसूरती को तरजीह दी जाती है, वहां भूमि के लिए खुद को स्वीकार करवाना चुनौतीपूर्ण था। भूमि ने व्हिस्टलिंग वुड्स इंटरनेशनल में एक्टिंग कोर्स में दाखिला लिया, लेकिन खराब उपस्थिति के कारण उन्हें वहां से निकाल दिया गया। हालांकि,इस झटके ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया।

'दम लगा के हईशा' से मिला बड़ा ब्रेक,30 किलो वजन बढ़ाया

भूमि ने लगभग 5-6 साल तक वाईआरएफ में काम किया और कई फिल्मों की कास्टिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इसी दौरान उन्हें कैमरे के सामने और पीछे दोनों की गहरी समझ मिली। इसी दौरान उन्हें फिल्म 'दम लगा के हईशा' के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला।यह फिल्म 2015 में रिलीज हुई और इसमें उन्होंने एक ओवरवेट लड़की 'संध्या' का किरदार निभाया। इस रोल के लिए उन्होंने करीब 30 किलो वजन बढ़ाया।

'दम लगा के हईशा' भूमि के करियर का टर्निंग पॉइंट

'दम लगा के हईशा' भूमि पेडनेकर के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने संध्या का किरदार निभाया, जो पारंपरिक सोच वाले समाज में आत्मसम्मान के साथ जीने वाली लड़की है। अपनी पहली ही फिल्म से भूमि ने साबित कर दिया कि वह ग्लैमरस लॉन्च नहीं, बल्कि दमदार अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में आई हैं।

यशराज फिल्म्स में असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर बनीं,शानू शर्मा ने दिया मौका

व्हिस्टलिंग वुड्स इंटरनेशनल से निकाले जाने और लगातार मिल रहे रिजेक्शन के बीच उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वाईआरएफ में ऑडिशन दिया था। उस समय कंपनी की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा नई टीम बना रही थीं। भूमि की समझ, स्क्रिप्ट की पकड़ और कलाकारों को परखने की क्षमता देखकर उन्हें असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर रख लिया गया।

संध्या के किरदार के लिए 30-35 किलो वजन बढ़ाने की चुनौती

इस किरदार के लिए भूमि को जानबूझकर करीब 30-35 किलो वजन बढ़ाना पड़ा। यह फैसला आसान नहीं था। वजन बढ़ाना शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण था। समाज जहां पहले से ही उनके वजन को लेकर टिप्पणी करता था,वहीं अब उन्हें और अधिक आलोचना झेलनी पड़ी। भूमि ने कहती हैं कि उन्होंने यह रोल इसलिए चुना क्योंकि यह असली था। अगर एक सच्ची कहानी के लिए शरीर बदलना पड़े,तो उन्हें कोई अफसोस नहीं था।

'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' से कमर्शियल सिनेमा में मजबूत पहचान

'दम लगा के हईशा' के बाद भूमि को अक्षय कुमार के साथ 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' में बड़ा मौका मिला। इस फिल्म के बाद कमर्शियल सिनेमा में भी उनकी मजबूत जगह बन गई। अब वह सिर्फ कंटेंट फिल्म की अभिनेत्री नहीं,बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी भरोसेमंद नाम बन चुकी थीं।

अभिनेताओं को तैयारी के लिए समय मिलना जरूरी : सुप्रिया पाठक

बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के मां बनने के बाद उनके द्वारा कथित तौर पर 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की बात सामने आई। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में अलग-अलग सितारों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। कुछ कलाकारों ने दीपिका का समर्थन किया,जबकि कुछ ने इसे अव्यावहारिक बताया। इसी मुददे को लेकर अब वरिष्ठ अभिनेत्री सुप्रिया पाठक भी सामने आई हैं और उन्होंने कलाकारों के लिए संतुलित कामकाजी समय की जरूरत पर जोर दिया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सुप्रिया पाठक ने कहा कि कलाकारों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पर्याप्त तैयारी का समय मिलना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के रूप में उन्हें अंततः दर्शकों के सामने ही प्रदर्शन करना होता है,इसलिए तैयारी का समय न मिलना कलाकार के काम को प्रभावित कर सकता है। उनके मुताबिक यदि किसी कलाकार को खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने का अवसर नहीं मिलेगा, तो वह दर्शकों के सामने पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। सुप्रिया ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बात केवल महिला कलाकारों पर ही नहीं बल्कि पुरुष अभिनेताओं पर भी समान रूप से लागू होती है। सुप्रिया पाठक ने इस दौरान यह भी कहा कि महिलाओं और पुरुषों की चुनौतियां अलग-अलग होती हैं। उनके अनुसार अक्सर महिलाओं को एक ही समय में कई जिम्मेदारियों के बारे में सोचना पड़ता है, जबकि पुरुष आम तौर पर एक ही काम पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यही वजह है कि महिलाओं के लिए काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना और भी जरूरी हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं स्वभाव से ही सशक्त होती हैं, बस कई बार उन्हें अपनी क्षमता को पहचानने के लिए थोड़ी प्रेरणा की जरूरत होती है। इस विवाद पर निर्देशक अनुभव सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह गॉसिप पर विश्वास नहीं करते और उन्होंने खुद कभी दीपिका के साथ काम नहीं किया है। हालांकि जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, उनके अनुसार दीपिका एक पेशेवर और काम के प्रति समर्पित अभिनेत्री हैं। अनुभव सिन्हा का मानना है कि अगर किसी कलाकार की मांगें निर्माताओं को गलत लगती हैं तो उनके साथ काम न करने का फैसला लिया जा सकता है। उनके मुताबिक ऐसे मुद्दों को सार्वजनिक विवाद बनाने के बजाय आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में मतभेद होना सामान्य बात है। बता दें कि बॉलीवुड में पिछले कुछ समय से काम के घंटों और वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

सलमान खान के साथ जमेगी अब नयनतारा की जोडी

साउथ डायरेक्टर वामशी पैदिपल्ली बॉलीवड सुपर स्टार सलमान खान के साथ एक बड़ी एंटरटेनर फिल्म बना रहे हैं जिसकी हीरोइन नयनतारा हो सकती हैं। सलमान और नयनतारा की जोड़ी फैंस को पसंद आने वाली है।

साल 2003 में आई फिल्म जवान में नयनतारा को शाहरुख खान के साथ रोमांस करते हुए देखा था। अब नयनतारा की जोड़ी सलमान के साथ भी जमने वाली है। वामशी के इस प्रोजेक्ट को दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है ये एक पैन इंडिया हिंदी फिल्म होगी जिसमें जबरदस्त एंटरटेनमेंट होने वाला है। हालांकि, अभी इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नयनतारा को शाहरुख खान के साथ जवान में देखा गया था।

एक्ट्रेस की नॉर्थ इंडिया बेल्ट में कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं है। लेकिन उनके काम को पसंद किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। हालांकि कुछ के मुताबिक एक्ट्रेस का काम दीपिका के कैमियो के आगे फीका था। वामशी पैदिपल्ली की बात स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ इन्होंने कई साउथ की सफल फिल्में बनाई हैं। वामशी ने साल 2007 में आई फिल्म मुन्ना से डायरेक्शन में कदम रखा था। इसके बाद साल 2010 में आई फिल्म वृंदावन, 2014 में येवाडू , 2016 उपिरी, 2019 महर्षि बनाई। फिल्म महर्षि ने नेशनल अवॉर्ड तक जीता था। बता दें, सलमान खान का फिल्मी करियर पिछले कुछ सालों से खास नहीं चल रहा है। उनकी पिछली फिल्में किसी का भाई किसी की जान, सिकंदर,टाइगर 3 ऑडियंस को खास पसंद नहीं आई थी।

ऐसे में सलमान पर बेस्ट फिल्म देने का फैंस का प्रेशर है। फिल्म सिकंदर के बाद एक्टर ने अपने कुछ फैंस से मिले सुझाव पर विचार किया था। ऐसे में आने वाले दिनों में एक्टर को कई बड़े प्रोजेक्ट्स में देखा जा सकता है। सलमान फिलहाल बैटल ऑफ गलवान में बिजी हैं। इसके आलावा उनके पास वामशी के साथ फिल्म है जिसकी शूटिंग इस अप्रैल से शुरू होने की खबर है। फिल्म अगले साल तक ही थिएटर में रिलीज हो पाएगी।

इसके अलावा किक का सीक्वल किक 2 और बब्बर शेर जैसी फिल्में आने की खबर है। सलमान आने वाले दिनों में अपनी नई फिल्म की जानकारी दे सकते हैं। बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान सिकंदर जैसी फिल्म के बाद एक बड़ी हिट की तलाश में हैं। बैटल ऑफ गलवान के अलावा कई अन्य प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कई बड़ी फिल्मों की स्क्रिप्ट हैं।

बेदी की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी हायर करेगी प्रियंका

ग्लोबल अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेटी मालती की प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी हायर करने का फैसला लिया है। एक्ट्रेस का कहना है कि वह नहीं चाहतीं कि बिना अनुमति कोई उनकी बेटी की तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्ड करे। एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि जैसे-जैसे मालती बड़ी हो रही है, वह और उनके पति निक जोनस उसकी पहचान को लेकर पहले से ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि मालती बहुत घूमना-फिरना पसंद करती है और वे चाहते हैं कि लोग उसे सामान्य बच्चे की तरह देखें, न कि एक सेलिब्रिटी की बेटी के रूप में। उनका मानना है कि बच्चों को ऐसी परवरिश मिलनी चाहिए जिसमें वे लोगों से डरें नहीं और

दुनिया को खुले मन से समझ सकें। प्रियंका ने बताया कि वह नहीं चाहतीं कि उनकी बेटी लोगों को शक की नजर से देखना सीखे। उनके अनुसार दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, इसलिए बच्चों को जागरूक बनाना जरूरी है, लेकिन साथ ही उन्हें सही-गलत की समझ भी होनी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने मालती की सुरक्षा को लेकर कुछ अतिरिक्त कदम उठाने का निर्णय लिया। प्रियंका ने यह भी साझा किया कि एक घटना ने उन्हें सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने बताया कि एक बार मालती स्कूल से घर लौट रही थी, तभी एक अजनबी व्यक्ति उसका पीछा करते हुए घर तक आ गया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। इस घटना ने प्रियंका और निक दोनों को काफी परेशान कर दिया। इसके बाद उन्होंने तय किया कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी जरूरी है। प्रियंका और निक की बेटी मालती का जन्म भी काफी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हुआ था।

मालती प्रीमैच्योर बेबी थी और जन्म के समय उसकी हालत काफी नाजुक थी। निक जोनस ने पहले एक पॉडकास्ट में बताया था कि बेटी तय समय से पहले पैदा हुई थी और जन्म के वक्त उसका रंग बैंगनी पड़ गया था। उस समय दोनों बेहद चिंतित थे और कई दिनों तक अस्पताल में रहकर बेटी की देखभाल करते रहे।

उम्र बढने के साथ प्यार कम नहीं बल्कि गहरा होता है : सौरभ शुक्ला

उम्र के साथ प्यार कम नहीं होता, बल्कि वह और भी गहरा, खूबसूरत हो जाता है। यह कहना है बॉलीवुड अभिनेता और फिल्ममेकर सौरभ शुक्ला का। सौरभ की नई फिल्म जब खुली किताब इसी विचार को केंद्र में रखकर बनी है, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति की खुशहाल शादी की कहानी दिखाई गई है। बीते दिनों जी5 पर रिलीज फिल्म में गोपाल और अनुसूया नामक एक बुजुर्ग जोड़े की जिंदगी की कहानी दिखाई गई है, जो सालों से साथ निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि सब कुछ सेटल लगता है, लेकिन अचानक एक पुराना राज खुलने से उनके रिश्ते में उथल-पुथल मच जाती है। इस दौरान प्यार,लंबे समय का साथ, माफी और एक-दूसरे को फिर से समझने की कोशिश की भावनाएं दिल को छू लेती हैं। कहानी में कॉमेडी के साथ-साथ भावुक पल भी हैं। अभिनेता सौरभ शुक्ला ने बताया कि फिल्म बढ़ती उम्र में रोमांस और साथ रहने के विषय को खूबसूरती से दिखाती है, जो हिंदी सिनेमा में अभी भी बहुत कम देखने को मिलता है।

स्क्रिप्ट लिखते समय कई लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या युवा दर्शक बुजुर्ग कपल की कहानी पसंद करेंगे? लेकिन सौरभ को इस पर कभी शक नहीं हुआ। उन्होंने बताया,'फिल्म में उम्रदराज कपल बाहर से भले ही बड़े लगें, लेकिन मन से वे जवान हैं। जब कोई भावनात्मक बदलाव आता है, तो उनकी युवा दिनों की भावनाएं फिर जाग उठती हैं।

खेल समाचार

आईपीएल 2026...मुंबई इंडियंस ने शुरू किया अभ्यास,29 मार्च को होना है पहला मुकाबला

मुंबई,16 मार्च 2026। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 की तैयारी शुरु कर दी है। मुख्य कोच महेला जयवर्धने की देखरेख में टीम ने पहला सीजन का पहला ट्रेनिंग सेशन पूरा किया। जयवर्धने ने गेंदबाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे, लसिथ मलिंगा और फील्डिंग कोच कार्ल हॉपकिंसन के साथ अभ्यास सत्र को संचालित किया। टीम के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग और फिजियोथेरेपी स्टाफ भी मौजूद थे। जयवर्धने ने कहा, 'प्री-सीजन के पहले दिन हमेशा कुछ खास होता है। आप देखते हैं कि खिलाड़ी अंदर आते हैं, एनर्जी बनती है। मकसद मजबूत शुरुआत करना होता है। हमारे पास ऐसे लड़के हैं जो इस फ्रेंचाइजी को बेहतर तरीके से जानते हैं। कुछ नए चेहरे भी आए हैं। पहला दिन पूरे कैंपेन का माहौल तय करता है। हम चाहते थे कि हर कोई पहले सेशन से ही यह महसूस करे कि हम कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, और हम एक-दूसरे के लिए कैसे पेश आते हैं। ' उन्होंने कहा,'ओपनिंग सेशन टूर्नामेंट से पहले सीरियस काम की शुरुआत है। पहला सेशन हमेशा रोमांचक होता है, लेकिन यह गंभीरता की शुरुआत भी है। हम जानते हैं कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। सेशन निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक हुआ। स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों

को मूवमेंट ड्रिल,एजिलिटी रूटीन और फिटनेस असेसमेंट से गुजारा ताकि मुश्किल सीजन से पहले उनकी तैयारी का अंदाजा लगाया जा सके। नए आईपीएल कैंपेन से पहले तैयारियों के तेज होने के साथ ही आने वाले दिनों में बाकी टीम के कैंप में शामिल होने की उम्मीद है। मुंबई इंडियंस ने अपने सोशल मीडिया पेज पर ट्रेनिंग सेशन की कुछ झलकियां साझा की हैं। सेशन में शामिल होने वाले खिलाड़ियों में शार्दुल ठाकुर, मयंक मारकंडे,अल्लाह गजनफर,नमन धीर, राजा अंगद बावा,रॉबिन मिंज,शर्मा, मयंक रावत, मालेवार,मोहम्मद इजहार और अश्विनी कुमार शामिल रहे। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला 29 मार्च को अपने होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलेगी।

इस बार आईपीएल में सबसे अधिक छक्के लगा सकते है वैभव : अभिनव मुकुंद

नई दिल्ली,16 मार्च 2026। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभिनव मुकुंद ने कहा है इस बार आईपीएल में सबसे अधिक छक्के वैभव सूर्यवंशी लगायेंगे। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने पिछली बार आईपीएल में केवल 7 मैचों में 24 छक्के लगाए थे। घरेलू के साथ ही जिस प्रकार उन्होंने अंडर-19 टीम की ओर से आक्रामक क्रिकेट खेला है। उससे अंदाजा है कि वह आईपीएल में इस बार धमाका करेंगे। वहीं मुकंद ने कहा कि आरसीबी के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली इस सत्र में 168.8 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। विराट आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनका करियर स्ट्राइक रेट अभी 132.85 है। उनका सर्वश्रेष्ठ सत्र का स्ट्राइक रेट 2024 में 154.69 रहा था, जबकि पिछले आईपीएल में उन्होंने 144.71 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। वहीं मुकुंद ने कहा कि आईपीएल के के संभावित ब्रेकआउट स्टार राजस्थान के उभरते हुए तेज गेंदबाज अशोक शर्मा रहेंगे।

सिनर पहली बार इंडियन वेल्स चैंपियन,मेदवेदेव को हराया

विमेंस सिंगल्स में सबालेंका जीतीं,फाइनल में रायबाकिना को मात दी

नई दिल्ली,16 मार्च 2026। अमेरिका के कैलिफोर्निया में खेले गए इंडियन वेल्स ओपन में इटली के जैनिक सिनर और बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने खिताब जीता। मेन्स सिंगल्स के फाइनल में सिनर ने रूस के डैनियल मेदवेदेव को हराकर अपना पहला इंडियन वेल्स टाइटल जीता। वहीं,विमेंस सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर-1 आर्यना सबालेंका ने एलिना रायबाकिना के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की।

सिनर फेडरर और जोकोविच के क्लब में शामिल हुए : सिनर ने इस जीत के साथ हार्ड कोर्ट पर होने वाले सभी बड़े खिताब अपने नाम कर लिए हैं। इनमें छह एटीपी मास्टर्स 1000, निट्टो एटीपी फाइनल्स,ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन शामिल हैं। इससे पहले यह उपलब्धि सिर्फ रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के नाम थी। सिनर ने

2023 में टोरंटो में अपना पहला मास्टर्स 1000 खिताब जीता था और अगले तीन सालों के भीतर ही उन्होंने हार्ड कोर्ट के सभी बड़े एलीट खिताब अपने नाम कर लिए।

सिनर ने मेदवेदेव को 7-6, 7-6 से हराया : पूरे टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं हारा : जैनिक सिनर ने फाइनल में पहला सेट टाईब्रेक में 7-6 (8-6) से जीता। इसके बाद दूसरे सेट में भी कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन सिनर ने इसे 7-6 (7-4) से अपने नाम कर लिया। खास बात यह रही कि सिनर ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं गंवाया और सीधे सेटों में जीत दर्ज करते हुए पहली बार इंडियन वेल्स मास्टर्स वेल्स की ट्रॉफी अपने नाम की। विमेंस सिंगल्स का फाइनल में आर्यना सबालेंका ने एलिना रायबाकिना को 3-6, 6-3, 7-6 (8-6) से हराया। सबालेंका पहला सेट हार गई थीं,लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी की। तीसरे सेट के टाइ-ब्रेकर में मुकाबला इतना फंस गया था कि रायबाकिना के पास चैंपियनशिप पॉइंट था, लेकिन सबालेंका ने उसे बचाया और जीत हासिल की।

विधानसभा में उठा 3 छात्राओं के प्रेग्नेंट होने का मामला...विपक्ष ने किया सदन का बहिष्कार

शिक्षा मंत्री बोले...हॉस्टल में नहीं रहती तीनों स्टूडेंट

रायपुर,16 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के दौरान बीजापुर के गंगालूर स्थित पोटा केबिन की 3 छात्राओं के गर्भवती होने का मामला उठा। इस मुद्दे पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार के जवाब के बाद आसंदी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि तीनों स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रहती। मुद्दे पर चर्चा नहीं होने से नाराज विपक्षी विधायकों ने सदन में नारेबाजी करते हुए हंगामा किया और बाद में सदन से बहिष्कार कर दिया। इससे पहले अमानक चावल की खरीदी का मुद्दा सदन में गूंजा। विधायक ब्यास कश्यप ने करोड़ों रुपए के घटिया चावल खरीदे जाने और गुणवत्ता परीक्षण में लापरवाही का मामला उठाते हुए दोषियों पर कार्रवाई और स्त्रढ्क्र दर्ज करने की मांग की। मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि करीब 8153 क्विंटल अमानक चावल पाया गया है और कुछ अधिकारियों को निलंबित कर नोटिस जारी किया गया है, लेकिन जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सरकार पर लीपापोती का आरोप लगाते हुए सदन में हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। सदन में सक्ती जिले में धान उठाव नहीं होने का मुद्दा भी

उठा। विधायक रामकुमार यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि 17 जनवरी से धान का उठाव रोकने की वजह से किसानों का धान बारिश में खराब हुआ और करोड़ों का नुकसान हुआ। वहीं मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि धान की रिसाइक्लिंग रोकने के लिए अस्थायी तौर पर उठाव रोका गया था और 31 मार्च से पहले शेष धान उठा लिया जाएगा। सदन में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी इस फैसले और किसानों के नुकसान को लेकर सरकार से जवाब मांगा। साथ ही बस्तर संभाग के आंगनबाड़ी केन्द्रों की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठा। विधायक लखेश्वर बघेल ने बताया कि संभाग में 2209 आंगनबाड़ी केन्द्र बिना भवन के संचालित हो रहे हैं। 1021 भवन जर्जर हालत में हैं, जबकि बड़ी संख्या में केन्द्रों में पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि कई भवनों के निर्माण और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए स्वीकृतियां दी गई हैं और बजट की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जाएगा।

विधायक रामकुमार यादव के सवाल और मंत्री दयालदास के जवाब

- **विधायक रामकुमार यादव** - सक्ती जिला समेत पूरे प्रदेश में धान का उठाव 17 जनवरी से आपने रोक दिया। यह आपने खुद स्वीकार किया है। जबकि सक्ती जिले में बहुत सारे राइस मिल हैं। धान का उठाव नहीं होने पर बारिश में धान खराब हो जाता है। इतने राइस मिल होने के बाद भी धान का उठाव क्यों रोका गया।
- **मंत्री दयालदास बघेल** - धान की रिसाइक्लिंग न हो,इस कारण धान का उठाव रोका गया था।
- रामकुमार यादव - धान का उठाव नहीं होने की वजह से धान पानी में भीग जाता है और इसका खामियाजा गरीबों को उठाना पड़ता है। गलती सरकार और अधिकारियों की है। बताया गया है कि सक्ती जिले में 30 करोड़ रुपए का धान चूहों ने खा लिया। क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
- **दयालदास बघेल** - सक्ती जिले में 47.41 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। इसमें से 44.25 लाख क्विंटल धान का उठाव हो चुका है। केवल 3.16 लाख क्विंटल धान का उठाव बाकी है। 31 मार्च से पहले धान उठा लिया जाएगा।
- **चरणदास महंत** - मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि धान की रिसाइक्लिंग होती थी। इसका मतलब विभाग ने इसे स्वीकार किया है। जहां-जहां रिसाइक्लिंग की सूचना मिली, वहां क्या कार्रवाई की गई।
- **दयालदास बघेल** - निर्णय यह था कि रिसाइक्लिंग न हो, इसलिए धान का उठाव रोक दिया गया।
- **चरणदास महंत** - 17 जनवरी को धान खरीदी बंद करा दी गई,जबकि 31 जनवरी तक धान खरीदी होनी थी। इस बीच जिन किसानों के पास टोकन थे,वे भी अपना धान नहीं बेच पाए। इस वजह से 600 करोड़ रुपए का धान नहीं बिक सका। इसके लिए कौन जवाबदार होगा।
- **दयालदास बघेल** - मैंने धान खरीदी की बात नहीं कही थी, बल्कि धान के उठाव को रोकने की बात कही थी। धान खरीदी 17 जनवरी को बंद नहीं की गई थी।

विधायक लखेश्वर बघेल के सवाल और मंत्री राजवाड़े के जवाब

- विधायक लखेश्वर बघेल-बस्तर संभाग में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र कब से संचालित हो रहे हैं।
- मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े-इसकी जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगी।
- लखेश्वर बघेल-बस्तर संभाग में 2209 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं, 1021 भवन जर्जर स्थिति में हैं। 3445 केन्द्रों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है और 4200 केन्द्रों में शौचालय उपलब्ध नहीं है। सरकार नर्सरी कक्षाएं शुरू करना चाहती है,लेकिन बिना भवन,पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं के यह कैसे संभव होगा।
- लक्ष्मी राजवाड़े-कई भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। पेयजल और शौचालय की व्यवस्था के लिए भी स्वीकृतियां मिली हैं।
- लखेश्वर बघेल-15 साल हो गए,लेकिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन नहीं बन पाए हैं। इसके लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए।
- लक्ष्मी राजवाड़े - बजट की उपलब्धता के अनुसार भवन निर्माण और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कराई जाएगी।

छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस संतोष सिंह सीआईएसएफ में बनेंगे डीआईजी

2011 बैच के अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए

रायपुर,16 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी संतोष सिंह अब दिल्ली में अपनी सेवाएं देंगे। केंद्र सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को उनकी प्रतिनियुक्ति को लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिया। वे छत्तीसगढ़ के कई चुनौतीपूर्ण जिलों में कप्तानी कर चुके हैं। विशेष रूप से रायपुर एसएसपी के रूप में उनके कार्यकाल को काफी सराहा गया था। वर्तमान में वे पुलिस मुख्यालय में डीआईजी के महत्वपूर्ण पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे।

'निजात' अभियान से बनाई देशभर में पहचान : आईपीएस संतोष सिंह केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने नवाचारों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने नशामुक्ति के लिए शुरू किए गए 'निजात' अभियान की तारीफ केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। कोरिया, राजनांदगांव और कोरबा जैसे जिलों में एसपी रहते हुए उन्होंने अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई है।

सीआईएसएफ में मिली अहम जिम्मेदारी : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, जैसे हवाई अड्डों, परमाणु संस्थानों और मेट्रो की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। संतोष सिंह को पांच साल के लिए या अगले आदेश तक के लिए इस बल में डीआईजी के पद पर पदस्थापित किया गया है। माना जा रहा है कि उनकी कार्यक्षमता और अनुभव को देखते हुए केंद्र ने उन्हें इस महत्वपूर्ण सुरक्षा विंग के लिए चुना है।

आज विधानसभा घेराव करेगी कांग्रेस

विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस ने बैठक की,दीपक बैज ने पदाधिकारियों के सौंपी जिम्मेदारी

रायपुर,16 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करेगी। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। घेराव की रणनीति पर चर्चा की गई। खास तौर पर पुलिस बंदोबस्त के बीच किस तरह से प्रदर्शन को संगठित और प्रभावी बनाया जाए, इस पर विस्तार से विचार किया गया। इसके साथ ही जिलाध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई। कांग्रेस का कहना है कि 17 मार्च को होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग शामिल होंगे।

मनरेगा और स्थानीय मुद्दों को लेकर घेराव

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि, मनरेगा बचाओ संग्राम और प्रदेश के कई स्थानीय मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसमें बिजली दरों में बढ़ोतरी, किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करना, धान खरीदी में वादाखिलाफी और गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी महासचिव सचिन पायलट सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। घेराव की तैयारियों को लेकर प्रदेश मुख्यालय में पहले भी दो बैठकें हो चुकी हैं। अब जिलों में भी लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

मनरेगा को लेकर लगातार जारी है प्रदर्शन

मनरेगा को लेकर कांग्रेस पहले भी आंदोलन कर चुकी है। दिल्ली में हुई पार्टी बैठक के बाद रायपुर में मनरेगा बचाओ संग्राम समिति की अहम बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू और पूर्व मंत्री उमेश पटेल मौजूद रहे थे। बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए थे। 30 जनवरी को प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर चक्का जाम किया गया। इसके बाद 31 जनवरी से 7 फरवरी तक प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा और अन्य मुद्दों को लेकर उसका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में 29 आबकारी अधिकारियों पर अभियोजन की मंजूरी,गिरफ्तारी की आशंका.....

रायपुर,16 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। ईडी को मिली अभियोजन स्वीकृति जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय को इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियोजन की अनुमति मिल गई है। मंजूरी मिलने के बाद जांच एजेंसी अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

गिरफ्तारी की बढ़ी संभावना

अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी या अन्य सख्त कार्रवाई की संभावना भी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने के साथ कुछ अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ सकता है।

मंत्रालय में लंबित थी फाइल

सूत्रों के अनुसार इस मामले से जुड़ी फाइल लंबे समय से मंत्रालय में लंबित थी। हाल ही में मंत्री के हस्तक्षेप के बाद फाइल को मंजूरी दी गई, जिसके बाद यह कार्रवाई संभव हो सकी। अब इस मामले में आगे की जांच में तेजी आएगी।

बारहवीं के हिंदी विषय का पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज

रायपुर,16 मार्च 2026। बारहवीं के हिंदी विषय का पेपर लीक के कथित आरोप की जाँच के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पुलिस और साइबर सेल में एफ आई आर दर्ज कराई है। बता दें कि एनएसयूआई का दावा है कि जो प्रश्न उस व्हाट्सऐप ग्रुप में साझा किए गए थे। वही सवाल अगले दिन 14 मार्च को आयोजित हिंदी के प्रश्नपत्र में लगभग उसी क्रम में पूछे गए। संगठन का कहना है कि इससे स्पष्ट होता है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो चुका था, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय का घेराव भी किया। संगठन ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि यह पता चल सके कि प्रश्नपत्र लीक होने के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं।

मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सिंधी सेवा महापंचायत द्वारा आयोजित 'चन्द्र जी रात, सिंधिन जो मेलो-आनंद मेलो' में हुए शामिल

सिंधी समाज का इतिहास पुरुषार्थ, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक : सीएम साय

रायपुर,16 मार्च 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर स्थित बीटीआई मैदान में छत्तीसगढ़ सिंधी सेवा महापंचायत द्वारा आयोजित 'चन्ड्र जी रात,सिंधिन जो मेलो-आनंद मेलो' में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सिंधी समाज का इतिहास पुरुषार्थ और साहस का इतिहास है। विभाजन की विभीषिका की पीड़ा सबसे अधिक सिंधी समाज ने झेली। उस कठिन समय में आपके पूर्वजों ने अपनी संपत्ति छोड़ी, अपना घर छोड़ा, लेकिन अपना आत्मसम्मान और परिश्रम करने का स्वभाव कभी नहीं छोड़ा। शून्य से शिखर तक कैसे पहुँचा जाता है, यह सिंधी समाज ने आज पूरी दुनिया को सिखाया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की

तरक्की में सिंधी समाज की प्रमुख भूमिका रही है। चाहे वह चेंबर ऑफ कॉमर्स हो या प्रदेश का छोटा-बड़ा व्यापार, आपकी मेहनत से राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। आप केवल व्यापार ही नहीं करते, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं।भविष्य में हमने विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का जो सपना देखा है, उसमें सिंधी समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने लगभग ढाई वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के तहत किए गए अधिकांश वादों को पूरा कर लिया है और लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज बी.टी.आई. ग्राउंड में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, वह बताता है कि सिंधी समाज अपनी जड़ों से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। 'सिंधियत जो मेलो' जैसे आयोजन हमारी नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति,खान-पान और सिंधी भाषा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें पवित्र शदाणी दरबार में संतों का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ जो स्नेह और आत्मीयता उन्हें मिली, वही अपनापन आज यहाँ भी महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज की यही एकजुटता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी प्रदेशवासियों को चेट्रीचंड्र पर्व की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर मुख्य मंच से सिंधु दर्शन यात्रा का भी विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ सिंधी सेवा महापंचायत को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, धमतरी महापौर रामू रोहरा, छत्तीसगढ़ सिंधी सेवा महापंचायत अध्यक्ष अमर गिदवानी, श्रीचंद सुंदरानी सहित सिंधी समाज के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1.25 करोड़ की ठगी के मामले में रेंज सायबर सेल को मिली बड़ी कामयाबी,मुख्य आरोपी को हरियाणा से किया गिरफ्तार

रायपुर,16 मार्च 2026। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत कार्रवाई करते हुए रेंज सायबर सेल पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 58 लाख रुपये पीड़ित को वापस दिलाए जा चुके हैं,जबकि शेष राशि आरोपियों के विभिन्न बैंक खातों में होल्ड कर दी गई है। रायपुर में रहने वाले सपन कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात मोबाइल नंबरों से कॉल कर कुछ लोगों ने स्वयं को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। उन्होंने प्रार्थी के क्रेडिट कार्ड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा मामला दर्ज होने की बात कहकर उसे डराया-धमकाया। इसके बाद ठगों ने प्रार्थी को करीब 24 घंटे तक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर जुड़े रहने के लिए मजबूर किया और

उसे डिजिटल अरेस्ट में रखकर लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपये की ठगी कर ली। मामले में विधानसभा थाना में धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया। जांच के दौरान पता चला कि ठगी की राशि को कई लेयर के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। पुलिस ने तत्काल इन खातों की पहचान कर राशि को होल्ड करा दिया। इसके बाद न्यायालय के माध्यम से 58 लाख रुपये पीड़ित को वापस कराए गए। शेष राशि भी आरोपियों से जुड़े विभिन्न बैंक खातों में होल्ड कर दी गई है, जिस पर आगे कानूनी कार्रवाई जारी है। जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी सोमनाथ महतो है।

घटना के बाद वह लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को दिल्ली और हरियाणा भेजा गया। लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने उसे गुड़गांव, हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सोमनाथ महतो (27 वर्ष),आर मंगलम यूनिवर्सिटी,सोहना,गुड़गांव का रहने वाला है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है।

गरियाबंद में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला,3 आरक्षकों की हालत नाजुक

गरियाबंद,16 मार्च 2026। ज़िले से सनसनीखेज मामला आया है। यहाँ अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर शराब बनाने वाले अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया है। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से एक जवान को देखते हुए उसे रायपुर रेफर किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, पूरा मामला गरियाबंद के कोसमी गांव का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में अवैध शराब बनाने और बेचने का बड़ा कारोबार चल रहा है। इस सूचना पर मैनपुर थाने से तीन पुलिसकर्मी मौके पर कार्रवाई करने पहुंचे। जैसे ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, मौके पर मौजूद शराब बनाने वालों ने एकजुट होकर पुलिस टीम को घेरकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में तीनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हुए पुलिसकर्मियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद एक जवान को रायपुर रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मैनपुर थाना पुलिस ने इस मामले में नामजद 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

खेत में काम कर रही महिलाओं पर मधुमक्खियों ने किया हमला,एक की मौत

दुर्ग,16 मार्च 2026। जिले के धमधा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रूहा में मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक खेत में काम कर रही महिलाओं पर हमला कर दिया। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई,जबकि चार से पांच अन्य महिलाएं घायल हो गईं। हादसे के बाद गांव में शोक और दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार खेत में काम के दौरान अचानक मधुमक्खियों का झुंड महिलाओं पर टूट पड़ा। हमले में 40 वर्षीय दुर्गा साहू,पति रामकुमार साहू गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तत्काल अन्य घायलों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धमधा ले जाया गया,जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दुर्गा साहू को मृत घोषित कर दिया। हमले में घायल अन्य

महिलाओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि खेतों के आसपास कई जगह मधुमक्खियों के बड़े-बड़े छत्ते लगे हुए हैं, जिससे इस तरह की घटनाओं का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि खेतों और गांव के आसपास लगे मधुमक्खी के छत्तों को हटाया जाए,ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)